

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 06, शुक्रवार, शाके 1945-जुलाई 28, 2023 <i>Shavana 06, Friday, Saka 1945- July 28, 2023</i>	

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान वित्त निगम
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 26, 2023

संख्या आरएफसी/एफ.पीए 23 (16)/469 :- दी स्टेट फाईनेन्सियल कारपोरेशन्स एक्ट, 1951 की धारा 48 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान वित्त निगम के संचालक मण्डल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से विचार विमर्श के पश्चात तथा राज्य सरकार की पूर्वानुमति लेकर राजस्थान वित्त निगम कर्मचारी पेंशन विनियम, 2023 की संरचना की है, जिसका विस्तृत पाठ्य निम्नानुसार होगा :-

राजस्थान वित्त निगम कर्मचारी पेंशन विनियम (रेग्यूलेशन)

अध्याय-1 प्रारम्भिक

1. शीर्षक एवं लागू होने की तिथि

- ये विनियम राजस्थान वित्त निगम कर्मचारी पेंशन विनियम 2023 कहलायेंगे।
- ये विनियम इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी होंगे।

2. लागू होना (DATE OF COMMENCEMENT) :

इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित (Otherwise Provided) के सिवाय ये विनियम निम्नांकित कार्मिकों पर लागू होंगे -

- वे सभी कर्मचारी जिन्हें निगम द्वारा विधिवत रूप से नियुक्त किया था/ हैं/ होंगे तथा जो इन विनियमों हेतु विकल्प (Option) देंगे। ऐसे विकल्प सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के पश्चात ही मान्य होंगे।

3. उपरोक्त विनियम निम्नांकित पर लागू नहीं होंगे :

- वे कार्मिक जो राजस्थान वित्त निगम में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।
- वे कार्मिक जो पार्ट टाइम बेसिस या फिक्स पारिश्रमिक पर कार्य कर रहे हैं।

- (iii) अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति, आकस्मिक, दैनिक मजदूरी, अप्रेंटिस एवं कार्य प्रभारित (Work Charge) अथवा उपरोक्त विनियम 2 में वर्णित के अतिरिक्त नियोजन में हैं।
- (iv) ऐसे कर्मचारी जो पूर्व विनियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं वे इस योजना में पात्र नहीं होंगे।

4. विनियम के संशोधन के अधिकार :

विनियम में संशोधन के सम्पूर्ण अधिकार बोर्ड में निहित होंगे।

5. विनियमों की व्याख्या एवं छूट देने का अधिकार :

विनियमों की व्याख्या एवं छूट देने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित होगा एवं निदेशक मण्डल (Board of Directors) का निर्णय कर्मचारियों एवं निगम पर बाध्यकारी होगा।

6. परिभाषायें : इन विनियमों में जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (i) **निगम** से अभिप्राय राजस्थान वित्त निगम से है।
- (ii) **निगम बोर्ड** से अभिप्राय होगा राजस्थान वित्त निगम निदेशक मण्डल के निदेशक (Board of Directors)
- (iii) **राज्य सरकार** से अभिप्राय होगा राजस्थान सरकार
- (iv) **सक्षम प्राधिकारी** से अभिप्राय होगा राजस्थान वित्त निगम के निदेशक मण्डल के डायरेक्टर्स (Board of Directors) अथवा वे प्राधिकारी जिन्हें बोर्ड द्वारा उपरोक्त विनियम के संबंध में शक्तियां प्रदान की गई हैं।
- (v) **कर्मचारी** से अभिप्राय होगा वह व्यक्ति जो राजस्थान वित्त निगम द्वारा वित्त निगम के कार्यों हेतु समय वेतनमान (टाइम स्केल)/ग्रेड-पे/पे-मैट्रिक्स पर राजस्थान वित्त निगम (स्टॉफ) विनियम 1958 के अंतर्गत विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पद पर नियुक्त किया गया है।
- (vi) **वेतन** से अभिप्राय राजस्थान वित्त निगम कर्मचारी द्वारा प्राप्त किये जाने वाले निम्न अंकित मासिक वेतन से है:-
 - (i) वेतन, विशेष वेतन या उसकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर समय-समय पर संशोधित वेतनमान में स्वीकृत वेतन के अतिरिक्त जो उसके द्वारा स्थाई या स्थानापन्न रूप से धारण किये गये पद के लिए स्वीकृत किया गया है, या जिसे वह अपनी पदीय स्थिति के कारण प्राप्त करने का पात्र है, एवं
 - (ii) विशेष वेतन एवं व्यक्तिगत वेतन, एवं
 - (iii) अन्य राशि जो राज्य सरकार के नियमों के तहत निदेशक मण्डल (Board of Directors) की अनुमति के अनुसार विशेष रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत की गई हो।
- (vii) **पेंशन** से अभिप्राय राजस्थान वित्त निगम की सेवा से सेवानिवृत्त हुए कार्मिक एवं उसके परिवार के सदस्य जिन्हें प्रतिमाह उक्त विनियम के प्रावधानानुसार राशि देय है।
- (viii) **अर्हकारी सेवा** (Qualifying Service) से कर्तव्य पर या अन्य प्रकार से की गई ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो इस विनियम के अधीन स्वीकार्य पेंशन एवं ग्रेच्युटी के लिए गिनी जायेगी।

- (ix) ग्रेच्युटी में निम्नलिखित सम्मिलित है - (i) सेवा ग्रेच्युटी (ii) सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी एवं (iii) अवशिष्ट ग्रेच्युटी (Residuary Gratuity)
 - (x) परिवार पेंशन से अभिप्राय इन विनियम के अधीन स्वीकार्य परिवार पेंशन से अभिप्रेत है।
 - (xi) पेंशन निधि से अभिप्राय राजस्थान वित्त निगम द्वारा पेंशन हेतु बनाई गई निधि से है।
 - (xii) निर्धारित तिथि से अभिप्राय निगम द्वारा निर्धारित दिनांक से है।
 - (xiii) विहित प्रारूप से अभिप्राय राजस्थान वित्त निगम कर्मचारी पेंशन विनियमन, 2023 एवं राजस्थान वित्त निगम कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि विनियमन, 2023 के विहित प्रारूपों से है जो अनुलग्नक-अ (Annexure "A") में दर्शाये गये हैं। इन प्रारूपों में यथा आवश्यकतानुसार संशोधन का अधिकार प्रबन्ध निदेशक में निहित होगा।
7. **निगम में जी.पी.एफ.लिंकड पेंशन स्कीम तथा उसके अंतर्गत पेंशन निधि :**
- (i) निगम में जी.पी.एफ.लिंकड पेंशन स्कीम लागू होगी।
 - (ii) इस हेतु पेंशन निधि का गठन किया जायेगा। यह पेंशन निधि राज्य सरकार के पी.डी.खाते में ही संधारित होगी।
8. **पेंशन योजना हेतु विकल्प :**
- (i) निगम के स्तर पर आवश्यक स्वीकृतियां तथा जी.पी.एफ.लिंकड पेंशन स्कीम संशोधनों सहित लागू होने के उपरांत सेवानिवृत्त कर्मिकों एवं सेवारत कर्मिकों से उपरोक्त पेंशन योजना हेतु निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान वित्त निगम के प्राधिकृत अधिकारी को नियत दिनांक तक पेंशन योजना के पुनर्विकल्प/विकल्प हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
 - (ii) निगम से सेवानिवृत्त हुए कर्मिक और उनकी मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशन हेतु पात्र आश्रित तथा वर्तमान में कार्यरत कर्मिक जो यह विकल्प देना चाहते हैं वे विकल्प पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित समयावधि में शाखा प्रभारी (Incharge Branch)/ मुख्यालय में प्रबन्ध निदेशक द्वारा विकल्प प्राप्त करने हेतु अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
 - (iii) निगम में पूर्व में सेवारत कर्मिक ने यदि अपने सेवाकाल में विकल्प के आधार पर पेंशन योजना एवं सी.पी.एफ.योजना अथवा सिर्फ सी.पी.एफ. योजना का विकल्प दिया था और अब सेवानिवृत्ति के बाद इन विनियमों के अंतर्गत विधिवत विकल्प पुनः प्रस्तुत कर देता है तो ऐसे सेवानिवृत्त कर्मिक (निगम में पूर्व में लागू पेंशन नियमों के अंतर्गत लाभ ले रहे पेंशनर्स के अतिरिक्त) इन विनियमों के अंतर्गत पुनर्विकल्प प्रस्तुत कर सकेगा। इसी प्रकार वर्तमान में सेवारत कर्मिकों द्वारा भी अपने पूर्व विकल्प में संशोधन हेतु अब उपरोक्त पेंशन योजना का पुनर्विकल्प दिया जा सकेगा।
 - (iv) सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मिक द्वारा एक बार दिया गया पुनर्विकल्प/विकल्प आवेदन अंतिम होगा तथा निर्धारित तिथि तक विकल्प प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जाएगा कि वह इस पेंशन विनियम के अंतर्गत नहीं आना चाहता। ऐसा कर्मिक पेंशन लाभों का हकदार नहीं होगा, परन्तु यदि कर्मिक द्वारा कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में यह माना जायेगा कि वह सी.पी.एफ.योजना का ही सदस्य बना रहना चाहता है।
 - (v) निगम में जीपीएफ लिंकड पेंशन स्कीम लागू होने के उपरांत नियमित वेतनमान में नियुक्त होने वाले कर्मिकों पर जीपीएफ लिंकड पेंशन स्कीम के प्रावधान ही लागू रहेंगे।

- (vi) सेवा से निष्काशित, सेवा से हटाये गये, सेवा से त्याग-पत्र देने वाले कार्मिकों को इस विनियम के अंतर्गत विकल्प की सुविधा नहीं होगी।
- (vii) इस संबंध में सम्पूर्ण कार्यवाही एवं रिकॉर्ड संधारण निगम की कार्मिक एवं प्रशासनिक शाखा, मुख्यालय द्वारा किया जायेगा।

9. सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा पेंशन विकल्प प्रस्तुत करने के साथ जमा कराये जाने वाली राशि :

(i)	सेवानिवृत्त कार्मिक को सी.पी.एफ. के नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की प्राप्त समस्त राशि उसको प्राप्त करने की तिथि से पेंशन निधि में वापस जमा कराने की तिथि तक 03 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एक मुश्त पेंशन निधि में जमा करानी होगी।
(ii)	यदि सी.पी.एफ. कटौती में से नियोक्ता अंशदान की कोई भी राशि किसी अन्य फण्ड/स्कीम में जमा थी और उसका भुगतान सेवानिवृत्त कार्मिक ने प्राप्त किया है तो ऐसी राशि को सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा उसकी प्राप्ति की तिथि से निगम की पेंशन निधि में 12 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज सहित निर्धारित दिनांक तक एक मुश्त जमा करानी होगी।
(iii)	यदि सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा कार्यरत अवधि के दौरान सी.पी.एफ. से नियोक्ता अंशदान की राशि का अंतिम प्रत्याहरण किया है तो प्रत्याहरण की तिथि से पेंशन निधि में राशि जमा कराने की तिथि तक आहरित की गई समस्त राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित निर्धारित दिनांक तक एक मुश्त जमा करानी होगी।
(iv)	सेवानिवृत्त कार्मिक को नियोक्ता अंशदान की भुगतान की गई राशि की वास्तविक तिथि से ब्याज की गणना की जाएगी। ब्याज की गणना पेंशन निधि में वास्तविक रूप से राशि जमा कराने की तिथि तक की अवधि के लिए की जायेगी। यदि सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा सी.पी.एफ. के अंतर्गत पेंशन विनियम में निर्धारित परिलाभ से अधिक परिलाभ प्राप्त किया हो तो उस अंतर राशि को भी 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से सेवानिवृत्त कार्मिक को पेंशन निधि में निर्धारित दिनांक तक जमा कराना होगा।
(v)	यदि सेवानिवृत्त कार्मिक के वेतन में संशोधन के कारण बाद में नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज के राशि प्राप्त हुई हो अथवा भविष्य में प्राप्त हो, तो उस सी.पी.एफ. के नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की समस्त राशि पेंशन निधि में जमा कराने की तिथि तक 03 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एकमुश्त पेंशन निधि में जमा कराई जायेगी।
(vi)	निगम में जिन कार्मिकों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प लिया था और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प को स्वीकार करने की स्थिति में एक्सग्रेसिया या अन्य रूप में अतिरिक्त राशि दी गई थी, उन कार्मिकों द्वारा उपरोक्त पेंशन योजना का विकल्प दिये जाने की स्थिति में भुगतान की गई ऐसी समस्त अतिरिक्त राशि में से आयकर की भुगतान की गई राशि को घटाकर शेष राशि की 50 प्रतिशत राशि को भी उस राशि को भुगतान करने की तिथि से जमा कराने की तिथि तक 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से पेंशन निधि में निर्धारित दिनांक तक एकमुश्त जमा करानी होगी।
(vii)	यदि निगम में कार्मिकों द्वारा सेवानिवृत्ति के उपरांत भी सी.पी.एफ. की राशि निगम से प्राप्त नहीं की है तो ऐसे मामलों में सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानकर सेवानिवृत्त कार्मिक को सेवानिवृत्ति पर सी.पी.एफ. के नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की समस्त राशि पेंशन निधि

	में जमा कराने की तिथि तक 03 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एकमुश्त पेंशन फण्ड में जमा करवाई जायेगी अथवा संस्था स्तर से सीधे ही पेंशन निधि में सेवानिवृत्त कार्मिक की सहमति से हस्तांतरित की जायेगी। परन्तु किसी कर्मचारी को उसके विरुद्ध जांच/ अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित होने से सीपीएफ राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो उन प्रकरणों में प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर ब्याज भुगतान करने का बिंदु तय किया जावेगा।
(viii)	पारिवारिक पेंशन हेतु निगम में प्रचलित पेंशन विनियमों में मृतक कार्मिक के पात्र आश्रित भी विकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे।
(ix)	सेवानिवृत्त कार्मिक/सेवानिवृत्त कार्मिक के पात्र परिजन द्वारा विकल्प प्रस्तुत करने तथा नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की प्राप्त समस्त राशि मय 03 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के निर्धारित दिनांक तक एक मुश्त जमा कराने के उपरांत ही नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्विकल्प/विकल्प स्वीकार किया जायेगा।
(x)	जिन कार्मिकों द्वारा नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार तकनीकी त्याग पत्र दिया जाकर अन्य संस्थान में नवीन पद पर कार्यग्रहण किया है, उनके मामलों में नियमों के अनुसार परीक्षण उपरांत विकल्प स्वीकार करने के संबंध में प्रचलित पेंशन नियमों के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
(xi)	जिन कार्मिकों की मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार के पारिवारिक पेंशन के पात्र सदस्य द्वारा कार्मिक को अथवा उनके परिवार को प्राप्त CPF/EPF के नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की प्राप्त समस्त राशि उसके प्राप्त करने की तिथि से वापस जमा करवाने की तिथि तक 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एकमुश्त पेंशन निधि में जमा करवाई जायेगी।

10. सेवानिवृत्त कार्मिक की जी.पी.एफ.कटौती के संबंध में निर्देश :

- सेवानिवृत्त कार्मिकों से कार्मिक के अंशदान की कोई भी राशि सामान्य प्रावधायी निधि सैब (जी.पी.एफ.-सैब) में हस्तांतरित नहीं की जायेगी। उसका निस्तारण राजस्थान वित्त निगम द्वारा सी.पी.एफ. के प्रावधानों के अंतर्गत करेगी।
- जो कार्मिक दिनांक 30.06.2023 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके मामलों में कार्मिक के अंशदान की राशि सामान्य प्रावधायी निधि सैब (जी.पी.एफ.-सैब) में हस्तांतरित नहीं की जायेगी, उसका भी निस्तारण निगम सी.पी.एफ. के प्रावधानों के अंतर्गत करेगी।

11. सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन निर्धारण संबंधी निर्देश :

- सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा सी.पी.एफ. के स्थान पर जी.पी.एफ.लिंकड पेंशन स्कीम हेतु प्रस्तुत विकल्प के संबंध में राशि जमा होने तथा विकल्प स्वीकार होने के उपरांत सेवानिवृत्ति की तिथि से 31.03.2023 तक निगम में लागू प्रावधानों के अंतर्गत नोशनल फिक्सेशन (Notional Fixation) किया जाकर तदनुसार पेंशन दिनांक 01.04.2023 से निर्धारित की जायेगी।
- पेंशन का निर्धारण सेवानिवृत्त कार्मिक के सेवानिवृत्ति के समय प्रचलित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

12. सेवारत कार्मिक द्वारा पेंशन निधि में राशि जमा कराने के संबंध में निर्देश :

- (i) निगम द्वारा सेवारत कार्मिकों को सी.पी.एफ. योजना के अन्तर्गत भुगतान की गयी राशि (नियोक्ता अंशदान) निर्धारित ब्याज सहित पेंशन निधि के पी.डी. खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।
- (ii) इस योजना के प्रभावी होने के पश्चात उपरोक्त विनियम के अन्तर्गत विकल्प देने वाले कार्मिकों की मासिक भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान राशि पेंशन निधि में जमा की जायेगी।
- (iii) सेवारत कार्मिकों को सी.पी.एफ. की जो राशि मय ब्याज के निगम में या निगम द्वारा खोले गये पी.डी.खाते या बैंक खाते में जमा है, वह समस्त नियोक्ता अंशदान राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज सहित पेंशन निधि के पी.डी.खाते में हस्तांतरित की जायेगी।
- (iv) इन विनियमों के अनुसार सेवारत कार्मिकों हेतु नियोक्ता अंशदान की राशि कार्मिक के मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते की 12 प्रतिशत की दर से पेंशन निधि में जमा की जायेगी। पूर्व में निगम में नियोक्ता अंशदान की दर कम होने से नियोक्ता अंशदान की दर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत 12 प्रतिशत की जा सकेगी।
- (v) सेवारत कार्मिक जो विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) पर हैं, तो उन्हें भी निगम मुख्यालय में ही विकल्प हेतु आवेदन करना होगा, तथा इन निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही होगी।
- (vi) सेवारत कार्मिक की जो सेवा पेंशन योग्य है किन्तु किसी अवधि का वेतन किसी भी कारण से नहीं मिला है तो ऐसे मामले में इस अवधि के पूर्व के वेतन के आधार पर देय कटौती कार्मिक को स्वयं मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित पेंशन निधि में जमा निर्धारित दिनांक तक करानी होगी। यदि भविष्य में इस अवधि का निर्णय हो जाता है तो कार्मिक निगम से इस राशि को नियमानुसार प्राप्त कर सकेगा।
- (vii) यदि कोई निगम कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर अन्य निगम/बॉडी/संस्था/वैदेशिक सेवा या राज्य सरकार में चला जाता है तो लेने वाला संस्थान प्रतिमाह राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर पेंशन कंट्रीब्यूशन एवं सी.पी.एफ. नियोक्ता अंशदान की राशि निगम को भेजेगा। इसी प्रकार यदि कोई कर्मचारी अन्य निगम/बॉडी/ संस्था/वैदेशिक सेवा या राज्य सरकार से निगम में डेपुटेशन पर आता है तो निगम द्वारा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर प्रतिमाह पेंशन कंट्रीब्यूशन एवं सी.पी.एफ. नियोक्ता अंशदान की राशि कर्मचारी की पैतृक संस्था को भेजा जायेगा। दोनों ही स्थितियों में इनकी प्रति संबंधित कर्मचारी को भी दी जायेगी।
- (viii) यदि राज्य सरकार या अन्य संस्था का कर्मचारी निगम में अपनी सेवा को समाहित (Absorb) कराना चाहता है और निगम निदेशक मण्डल द्वारा इस समाहित (Absorb) किये जाने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी जाती है तो ऐसे कर्मचारी को निगम में तत्समय प्रचलित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ देय होंगे।

13. पेंशन भुगतान :

- (i) सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा सी.पी.एफ. के स्थान पर जी.पी.एफ.लिंकड पेंशन स्कीम का विकल्प स्वीकार करने तथा सम्पूर्ण राशि मय ब्याज के जमा होने की पुष्टि के बाद सेवानिवृत्ति की तिथि से दिनांक 31.03.2023 तक निगम में लागू प्रावधानों के अंतर्गत

- नोशनल फिक्सेशन किया जाकर तदनुसार पेंशन दिनांक 01.04.2023 से निर्धारित की जायेगी। जो कार्मिक दिनांक 01.04.2023 के बाद सेवानिवृत्त होंगे उनकी पेंशन उनकी सेवानिवृत्ति के उपरांत नियमानुसार देय होगी।
- (ii) पेंशन निधि के गठन हेतु निगम द्वारा कार्मिकों को देय नियोक्ता अंशदान राशि पेंशन निधि में सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत जमा की जायेगी।
- (iii) पेंशन निधि के गठन उपरांत प्राप्त राशि तथा तदुपरांत नियोक्ता अंशदान एवं ब्याज आदि से जमा होने वाली राशि से ही पेंशन परिलाभों का भुगतान किया जायेगा। पेंशन राशि का भुगतान उपलब्ध पेंशन फण्ड के अनुसार किया जाता रहेगा।
14. पुनर्विकल्प/विकल्प प्रस्तुत करने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक नियोक्ता अंशदान की राशि एवं उस पर उपरोक्तानुसार देय ब्याज की गणना एवं उसकी शुद्धता का समस्त दायित्व विकल्प स्वीकार करने वाले सक्षम प्राधिकारी का होगा।
15. प्रस्तुत पुनर्विकल्प/विकल्प पत्र के परीक्षण पश्चात पेंशन भुगतान आदेश (Pension Payment Order) प्रबन्ध निदेशक द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे।

अध्याय-2 सामान्य विनियम

16. पेंशन भावी सदाचरण के अध्यधीन होगी :

- (i) भावी सदाचरण इन विनियमों के अधीन पेंशन एवं उसको जारी रखने की प्रत्येक स्वीकृति की एक अंतरनीहित शर्त होगी।
- (ii) यदि पेंशनर किसी गम्भीर अपराध के लिए दोषी सिद्ध कर दिया गया है या यदि वह किसी गंभीर कदाचरण का दोषी पाया जाता है तो बोर्ड द्वारा पेंशन या उसके किसी भाग को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रोक सकेगा या वापस ले सकेगा।
- (iii) यदि किसी पेंशनर को गंभीर अपराध हेतु न्यायालय के अंतिम आदेश से दोषी करार दिया जाता है तो उपरोक्त संबंध में निर्णय न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष में लिया जायेगा।
- (iv) यदि उपरोक्त विनियम के (ii) के अंतर्गत कार्यवाही की जानी है तो जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी है उन्हें पेंशन स्वीकृति अधिकारी द्वारा एक नोटिस दिया जायेगा जिस पर वह अपना प्रत्युत्तर निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करेगा। जिस पर गुणावगुण के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- (v) यदि पेंशनर भावी सदाचरण की शर्त को पूरा नहीं करता है तो ऐसे प्रकरण में पेंशन मंजूरकर्ता प्राधिकारी यह समझे कि पेंशनर गम्भीर अवचार (Prima-facia Guilty of grave misconduct) का प्रथम दृष्टया दोषी है तो वह आवश्यक आदेश पारित करने के पूर्व निम्नलिखित कार्यवाही करेगा -
- (क) पेंशनर पर एक नोटिस तामील करायेगा जिसमें उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही का और उन कारणों का उल्लेख होगा जिनसे ऐसी कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है और उसे ऐसे नोटिस की प्राप्ति के एक माह (30 दिवस) के भीतर जो पेंशन मंजूरकर्ता अधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाये प्रस्ताव के विरुद्ध ऐसा अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने के लिए कहेगा।

(ख) पेंशनर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन यदि कोई हो पर विचार करेगा एवं अपनी संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

17.

(i) निगम के देयों की वसूली :

यदि किसी भी मामले में यह पाया जाये कि सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी के विरुद्ध निगम के देय बकाया हैं या उसके विरुद्ध तत्पश्चात बकाया पाये जाये तो कर्मचारी के विरुद्ध बकाया देयों की वसूली, उसको या यथास्थिति उसके परिवार को संदेय या संदत्त पेंशन/उपदान या दोनों या पेंशन के संराशीकृत मूल्य की रकम में से, उसको या उसके परिवार के सदस्य की सहमति लिए बिना की जा सकेगी। तथापि, कर्मचारी या, यथास्थिति, उसके परिवार के सदस्य को, उसके विरुद्ध बकाया पाये गये और उसकी पेंशन या उपदान/या दोनों में से वसूल किये गये देयों आदि के ब्यौरों की सूचना दी जाये।

स्पष्टीकरण: निगम के देय ऐसे वसूली योग्य हो सकते हैं जैसे वेतन और भत्तों या छुट्टी वेतन या वाहन/भवन अग्रिम यात्रा भत्ता या अन्य अग्रिमों की अधिक रकम की स्वीकृति जारी हो जाये या पेंशन/उपदान या पेंशन के संराशीकृत मूल्य पारिवारिक पेंशन आदि के गलत या संदाय सहित बकाया या वसूलीय पाये जाने वाले अन्य संदाय या देय।

(ii) पेंशन में से हानियों की वसूली

प्रबंध निदेशक को, पेंशन या उसके किसी भाग को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि तक के लिए रोके रखने या प्रत्याहृत करने की पूर्ण शक्तियां और निगम को हुई आर्थिक हानि की सम्पूर्णतः या भागत वसूली पेंशन में से करने का आदेश देने का अधिकार होगा, यदि कोई पेंशनर उसके सेवकाल के दौरान, जिसमें सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियोजन की कालावधि भी सम्मिलित है, गंभीर कदाचरण या उपेक्षा या निगम को हुई कोई भी हानि का विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों में दोषी पाया जाये:

(क) परन्तु ऐसी विभागीय कार्यवाहियां, यदि कर्मचारी के सेवा में रहते समय, चाहे सेवानिवृत्ति के पूर्व या उसके पुनर्नियोजन के दौरान, संरक्षित की जाती हैं, कर्मचारी की अंतिम सेवानिवृत्ति के पश्चात इस विनियम के अधीन की कार्यवाहियां समझी जायेंगी और उस प्राधिकारी द्वारा, जिसके द्वारा ये प्रारम्भ की गयी थी, उस रीति से चालू रखी और समाप्त की जायेंगी मानों कर्मचारी सेवा में बना रहा था।

(ख) ऐसी विभागीय कार्यवाहियां, यदि सेवा से उसके सेवानिवृत्त होने या पुनर्नियोजित नहीं रह जाने के पश्चात संरक्षित नहीं की गई थी तो:-

- (i) निगम संचालक मण्डल के अनुमोदन के सिवाय संरक्षित नहीं की जायेगी।
- (ii) सेवा काल में कारित ऐसे दोष के लिये ही की जावेगी जिसमें निगम को कर्मचारी की लापरवाही या अकर्मण्यता के कारण हानि हुई हो।
- (iii) ऐसी प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान पर संचालित की जायेगी जो सक्षम प्राधिकारी निगम के कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियों पर लागू प्रक्रिया के अनुसार निर्देशित करे और

- (iv) अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व निगम संचालक मण्डल से परामर्श किया जायेगा।
- (v) निगम को हुई कोई भी हानि के लिये संबंधित दोषी व्यक्ति से सेवानिवृत्ति लाभों/पेंशन से वसूली की जा सकेगी जो उसे सुनवाई का युक्तियुक्त मौका दिया जाकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णित की जावेगी।
- (vi) न्यायिक कार्यवाही निम्नानुसार प्रारम्भ की हुई समझी जायेगी -
- (क) आपराधिक कार्यवाहियों के मामले में, उस तारीख को जिसको शिकायत या पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट, जिस पर मजिस्ट्रेट संज्ञान ले, की गयी है, और
- (ख) सिविल कार्यवाहियों के मामले में, न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की तारीख को।
- (vii) उक्त प्रावधान पूर्व में जारी किसी आदेश/निगम के निदेशक मण्डल (Board of Directors) राज्य सरकार के निर्णय के अतिक्रमण में प्रभावी होंगे।

18. विभागीय, न्यायिक या अन्य कार्यवाहियां लंबित होने की दशा में अनंतिम/प्रोविजनल पेंशन (Provisional Pension)/प्रोविजनल ग्रेच्युटी (Provisional Gratuity) का संदाय (Payment of Provisional pension/provisional gratuity where departmental/judicial/ other proceedings are pending):

- i. जहां किसी ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध जो अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने के पश्चात या अन्यथा सेवानिवृत्त हो चुका है या उसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं तो उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से ऐसी कार्यवाहियों के समाप्त होने और अंतिम आदेश पारित किये जाने की तारीख तक की कालावधि के दौरान उसको ऐसी अधिकतम पेंशन से अनधिक अनंतिम/प्रोविजनल (Provisional Pension) संदत्त की जाएगी जो सेवानिवृत्ति की तारीख तक या वह सेवानिवृत्ति की तारीख को निलंबनाधीन (Suspend) था तो उस तारीख से जिसको उसको लंबित किया गया ठीक पूर्व की तारीख तक की अर्हक सेवा के आधार पर अनुज्ञेय होती, परन्तु यदि कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाही लंबित है तो प्रोविजनल पेंशन एवं प्रोविजनल रिटायरमेंट कम ग्रेच्युटी की पूर्व में भुगतान की गई राशि की वसूली की जा सकेगी अथवा राशि कम भुगतान होने पर शेष अंतर राशि पूर्व भुगतान की जा सकेगी, यदि कर्मचारी की अंतिम स्वीकृत पेंशन से यह राशि कम है या सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम की गई है, या कम बनी है, या स्थायी रूप से या कुछ समय के लिए रोकी गई है।
- ii. यदि कर्मचारी के विरुद्ध ऐसी विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है जिसमें दीर्घ शास्ती (major penalty) मिलने की संभावना है तो उसे 50 प्रतिशत ग्रेच्युटी मिल सकेगी, परन्तु दीर्घ शास्ती (major penalty)/क्रिमीनल केस में अंतिम निर्णय पर उस कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है तो उसे कोई ग्रेच्युटी देय नहीं होगी, परन्तु यदि प्रोविजनल ग्रेच्युटी दे दी गई है तो उसकी वसूल कर ली जायेगी,

परन्तु यदि लघु शास्ती (minor penalty) की जाती है तो 100 प्रतिशत ग्रेच्युटी दी जा सकती है।

- iii. यदि कर्मचारी के विरुद्ध कोई भूमि, भवन संबंधी ऋण/अग्रिम (Land and Building Loan/Advance) शेष है या राजकीय/आरएफसी निवास का किराया शेष है तो उसकी प्रोवीजनल पेंशन/ग्रेच्युटी से वसूली की जा सकेगी।

19. शास्ति के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति :

- i. शास्ति के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए निगम कर्मचारी को, ऐसी शास्ति आरोपित करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों, ऐसी दर पर स्वीकृत की जाएंगी जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को उसे स्वीकार्य पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों के दो-तिहाई से कम दर पर नहीं होगी या पूर्ण क्षतिपूरक पेंशन से अधिक नहीं होगी।
- ii. जब भी किसी कर्मचारी के मामले में प्रबंध निदेशक/सक्षम प्राधिकारी इन विनियमों के अधीन पेंशन की पूर्ण रकम से कम पेंशन स्वीकृत करने वाला कोई आदेश (चाहे प्रारम्भिक, अपीलिय या पुनर्वलोकन की शक्तियों का प्रयोग करते हुए) पारित करें तो ऐसा आदेश निगम के निदेशक मण्डल (Board of Directors) की स्वीकृति के अनुसार होगा। उक्त प्रावधान पूर्व में जारी किसी आदेश/निगम के निदेशक मण्डल (Board of Directors) के निर्णय के अतिक्रमण में प्रभावी होंगे।
- iii. उप-विनियम (i) के अधीन या, जैसी भी स्थिति हो, उप-विनियम (ii) के अधीन स्वीकृत की गई या दी गई पेंशन राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम पेंशन राशि संबंधी प्रावधानों के अनुसार (अपवादों सहित) निगम के निदेशक मण्डल (Board of Directors) के अनुमोदन अनुसार देय होगी।

20. परिसीमाएं (Limitations):

- (i) निगम कर्मचारी एक ही पद पर एक ही समय पर, या एक ही निरंतर सेवा द्वारा दो पेंशनें अर्जित नहीं कर सकता है।
- (ii) एक ही पद के संबंध में दो कर्मचारियों की सेवा साथ-साथ नहीं गिनी जायेगी।
- (iii) यदि किसी कर्मचारी ने अन्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी संगठन से पेंशन पहले ही आहरित कर ली है और निगम में भी पेंशन अर्जित करता है तो वह एक पेंशन पर केवल महंगाई भत्ता अर्जित करने का हकदार होगा। इस संबंध में राज्य सरकार में प्रचलित संशोधित व्यवस्था निगम के निदेशक मण्डल (Board of Directors) के अनुमोदन अनुसार लागू रहेगी।
- (iv) निगम कर्मचारी जो, अधिवार्षिकी पेंशन या निवृत्ति पेंशन पर सेवानिवृत्त हो जाने के बाद में पुनः नियुक्त हो जाता है, अपनी पुनर्नियोजन की अवधि के लिए पृथक पेंशन या ग्रेच्युटी के लिए हकदार नहीं होगा।

21. पेंशन के क्लेम कब स्वीकार नहीं किये जायेंगे :

- (i) जब कर्मचारी को एक सीमित समय या किसी विनिर्दिष्ट कर्तव्य के लिए नियुक्त किया जाता है तथा उस कर्तव्य की समाप्ति पर उसे सेवा से डिस्चार्ज कर दिया जाता है।

- (ii) यदि किसी व्यक्ति को बिना किसी विनिर्दिष्ट समय सीमा या ड्यूटी के दैनिक, साप्ताहिक या मासिक मजदूरी के आधार पर अस्थायी रूप से नियोजित किया गया परन्तु ऐसे व्यक्ति को उसकी सेवामुक्ति के लिए एक माह का नोटिस दिया जायेगा।
 - (iii) जब कोई कर्मचारी अनुबन्ध के अधीन नियुक्त किया जाता है।
22. यदि किसी कर्मचारी की निगम का कार्य सम्पादित करते हुए मृत्यु हो जाती है एवं वह पेंशन योग्य सेवा (Qualifying Service) के अभाव में पेंशन का पात्र नहीं हैं तो उसके परिवार को निदेशक मण्डल (Board of Directors) की स्वीकृति से एक्सग्रेसशिया का भुगतान किया जा सकता है। जो राज्य सरकार द्वारा अभिनिर्धारित राशि से अधिक नहीं होगा।

अध्याय - 3

पेंशन के प्रकार (Types of Pension)

23. पेंशन के प्रकार :

पेंशन के निम्नलिखित पांच वर्ग हैं:-

- (i) क्षतिपूर्ति पेंशन (Compensation Pension)
- (ii) अधिवार्षिक पेंशन (Superannuation Pension)
- (iii) स्वैच्छिक/अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन (Voluntary/Compulsory Pension)
- (iv) असमर्थता/विकलांगता पेंशन (Disability Pension)
- (v) परिवार पेंशन (Family Pension)

24. क्षतिपूर्ति पेंशन (Compensation Pension) मंजूर करने की शर्तें :

- (i) यदि किसी कर्मचारी का चयन, उसके स्थायी पद को समाप्त कर दिये जाने के कारण निगम की सेवा से सेवान्मुक्ति के लिए किया जाता है तो जब तक उसे ऐसे अन्य पद पर नियुक्त नहीं कर दिया जाये जिसकी शर्तें, उसको सेवान्मुक्त करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके स्वयं के पद की शर्तों के कम से कम बराबर नहीं समझी जायें, उसके लिए यह विकल्प होगा कि:-
 - (क) ऐसी क्षतिपूर्ति पेंशन या उपदान ले जिसके लिए वह की गयी सेवा के लिए हकदार हो, या
 - (ख) ऐसे वेतन पर अन्य नियुक्ति स्वीकार करे जो उसे प्रस्तावित की जाये और निगम में उसकी पूर्ववर्तीसेवा को पेंशन के लिए गिना जाना चालू रखे।
- (ii) किसी कर्मचारी को सेवामुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह स्थायी नियोजन में नियोजित कर्मचारी को, उसका पद समाप्त किये जाने या स्थापन में कमी किये जाने के कारण उसकी सेवा समाप्त करने के पूर्व, युक्तियुक्त नोटिस दे। यदि किसी भी मामले में कम से कम तीन मास का नोटिस नहीं दिया गया हो तो कर्मचारी तीन मास या उसे दिये गये वास्तविक नोटिस की कालावधि तीन मास से जितनी कम हो, उतनी कालावधि के वेतन और भत्तों का हकदार होगा। नोटिस कालावधि के वेतन और भत्ते ऐसी दर पर संदत्त किये जायेंगे जो वह तब आहरित करता जब सेवान्मुक्त न होकर सेवा में बना रहता। तथापि पेंशन उस कालावधि के लिए ही संदेय होगी जिसके संबंध में वह सेवामुक्ति के नोटिस के बदले

में उपदान प्राप्त करता है। किसी कर्मचारी के छुट्टी पर रहने या निलंबित रहने की दशा में सेवान्मुक्त करने का आदेश तब तक प्रवर्तन में नहीं लाया जायेगा जब तक कि छुट्टी समाप्त नहीं हो जाये या निलंबन प्रतिसंहत न कर लिया जाये।

25. अधिवार्षिकी पेंशन मंजूर करने की शर्तें :

- (i) अधिवार्षिकी पेंशन ऐसे कर्मचारी को मंजूर की जाती है जिसका राजस्थान वित्त निगम (स्टाफ) विनियमों के अधीन अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होना आवश्यक है।
- (ii) किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति उस माह की अंतिम तारीख को, जिस माह में वह अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करे, स्वतः हो जाती है परन्तु यदि किसी कार्मिक की जन्म दिनांक माह की एक तारीख को आती है तो उसकी सेवानिवृत्ति उसके ठीक पूर्व माह की अंतिम तारीख को हो जावेगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके प्रतिकूल विनिर्दिष्ट आदेशों के अभाव में वह नियत तारीख को सेवानिवृत्त हुआ समझा जायेगा, और उसको उस तारीख से, जिसको वह अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करता है के बाद के कोई वेतन और भत्ते अनुज्ञात नहीं होंगे। कर्मचारी, उसकी सेवा पुस्तिका में अभिलिखित जन्म तारीख के आधार पर अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने पर इस बात पर विचार किये बिना कि क्या औपचारिक सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये गये हैं या नहीं, नियत तारीख पर कार्यभार सौंप देगा।

26. स्वैच्छिक/अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन की मंजूरी की शर्त:

स्वैच्छिक/अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन ऐसे कर्मचारी को मंजूर की जाती है जो उक्त नियमों के अधीन सेवानिवृत्त हो गया है अथवा किया गया है।

27. 1 15 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति:

- (क) कोई कर्मचारी उसकी नियुक्ति करने वाले सक्षम प्राधिकारी को लिखित में कम से कम 3 मास का नोटिस देने के पश्चात उस तारीख से जिसको वह अर्हक सेवा के 15 वर्ष पूरे करता है या उसके पश्चात किसी भी तारीख से जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, सेवा से सेवानिवृत्त हो सकेगा।
- (ख) नियुक्ति प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह किसी ऐसे कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मंजूर नहीं करे –

(i)	जो निलंबनाधीन हो
(ii)	जिसके मामले में न्यायालय में अभियोजन करने का विचार हो या कर दिया गया हो,
(iii)	जिसके मामले में, सेवा से हटाने या पदच्युत करने की बड़ी शास्ति अधिरोपित करने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही लंबित हो या करने का विचार हो।

- (ग) कोई कर्मचारी, जिसने इस उप-विनियम के खण्ड (1) (क) के अधीन सेवानिवृत्ति चाहने के लिए नोटिस दिया है, सेवानिवृत्ति के नोटिस को स्वीकार कर लेने की उपधारणा कर सकेगा और सेवानिवृत्ति नोटिस के निबंधनों के अनुसार स्वतः प्रभावी होगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश नहीं कर दिया जाये और नोटिस की समाप्ति के पूर्व कर्मचारी पर तामील नहीं कर दिया जाये।

- (घ) कोई भी कर्मचारी, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन से, इस उप-विनियम के खण्ड (क) के अधीन दिये गये नोटिस को नोटिस की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय वापस ले सकेगा। किन्तु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश (order) जारी हो गया है तो वापस नहीं ले सकेगा।
- (ङ) कर्मचारी की नियुक्ति करने वाला सक्षम प्राधिकारी इस उप-विनियम के उप खण्ड (क) के अधीन अनुध्यात नोटिस प्रबन्ध निदेशक के पूर्व अनुमोदन से तीन मास से कम का भी स्वीकार कर सकेगा।

2. **15 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी होने के पश्चात अनिवार्य सेवानिवृत्ति:**

- (I) नियुक्ति करने में सक्षम प्राधिकारी को किसी भी कर्मचारी को लिखित में कम से कम तीन मास का पूर्व नोटिस देकर लोक हित में सेवा से उस तारीख को जिसको वह 15 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करता है या उस तारीख को जिसके वह 50 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, जो भी पहले हो, या उसके पश्चात किसी भी तारीख को सेवानिवृत्ति करने का पूर्ण अधिकार होगा, परन्तु ऐसे कर्मचारी को सेवा से तत्काल सेवानिवृत्त किया जाये और ऐसी सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी नोटिस के बदले में तीन मास के वेतन और भत्तों का प्राप्त करने का हकदार होगा।
- (II) यदि कर्मचारी पर सेवानिवृत्ति आदेश की पूर्व में तामील न हुई हो तो निगम सेवानिवृत्ति के ऐसे आदेश को राज्य स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करवा सकेगा और कर्मचारी ऐसा प्रकाशन होने पर स्वतः ही सेवानिवृत्त समझा जायेगा।
- (III) इस उप-विनियम के उपखण्ड (1) में सम्मिलित अधिकार का प्रयोग ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध किया जाना आशयित है जिसकी दक्षता का हास हो गया है या सत्यनिष्ठा शंकास्पद है। किन्तु जिसके विरुद्ध अदक्षता का औपचारिक आरोप लगाना वांछनीय नहीं है, इन उपबंधों का प्रयोग केवल ऐसे कर्मचारी के मामले में करने का आशय है जिसको रखे रहने के लिए व्यक्तिगत आधारों पर अयोग्य समझा जाये। इस उप-विनियम के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति एक शास्ति के रूप में नहीं है अपितु किसी कर्मचारी को कतिपय समय तक निगम में सेवा कर लेने के पश्चात सेवानिवृत्ति करने के निगम के आरक्षित अधिकार के प्रयोग के रूप में है। कर्मचारी के विरुद्ध औपचारिक कार्यवाहियों के लिए राजस्थान वित्त निगम (स्टाफ) विनियम, 1958 के तत्संबंधित विनियम में अधिकथित प्रक्रिया को ऐसे मामलों में लागू करना अभिप्रेत नहीं है।
- (IV) जहां किसी कर्मचारी को दक्षता में हास या शंकास्पद सत्यनिष्ठा के कारणों से इस उप-विनियम के अधीन सेवानिवृत्त किया जाये तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो निगम द्वारा समय-समय पर विहित की जाये।
- (V) इस उप-विनियम के उपबंध किसी ऐसे कर्मचारी पर भी लागू होंगे जो अभिदायी भविष्य निधि का सदस्य था। उसके मामले में पद "अर्हक सेवा" से उस तारीख से प्रारम्भ हुई सेवा अभिप्रेत है जिसको कर्मचारी ने भविष्य निधि में अभिदान करना प्रारम्भ किया।

28. **असमर्थता/विकलांगता पेंशन(Disability Pension) मंजूरी की शर्तें:**

- (1) विकलांगता पेंशन ऐसे कर्मचारी को मंजूर की जाती है जो निगम की सेवा से ऐसे शारीरिक या मानसिक शैथिल्य के आधार पर सेवानिवृत्त हो जिसके कारण वह निगम की सेवा के लिए स्थायी रूप से असमर्थ हो गया है। यदि असमर्थता असंयत या अनियमित आदतों अर्थात् मदिरापान या अनैतिक आदतों के कारण हो तो कोई पेंशन मंजूर नहीं की जायेगी।

- (2) विकलांगता पेंशन के दावे पर निगम के "अ" प्रवर्ग के कर्मचारियों के मामले में किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अन्य प्रवर्ग के कर्मचारियों के मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी या समतुल्य हैसियत के चिकित्सा अधिकारी की रैंक के अधिकारी द्वारा दिये गये असमर्थता के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर ही विचार किया जायेगा। जब निगम द्वारा ऐसे किसी कर्मचारी के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए विशेष अनुरोध किया जाये तो राज्य के सरकारी चिकित्सालय के प्रमुख द्वारा चिकित्सा बोर्ड गठित किया जा सकेगा और परीक्षण प्रभारों, यदि कोई हो, का संदाय निगम द्वारा किया जायेगा।

(क)	<p>चिकित्सा प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप निम्नलिखित होगा :-</p> <p style="text-align: center;">"क"</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि मैंने (हमने) राजस्थान वित्त निगम के अधिकारी/कर्मचारी श्री ----- पुत्र श्री ----- कथन के अनुसार ----- वर्ष है और देखने में ----- वर्ष लगता/लगती है।</p> <p>मैं (हम) श्री ----- को ----- उसके रोग या केस का विवरण के परिणामस्वरूप राजस्थान वित्त निगम में किसी भी प्रकार की और सेवा करने के लिए पूर्ण रूप से और स्थायी रूप से असमर्थ समझता हूँ/समझते हैं। उसकी असमर्थता मुझे (हमें) अनियमित या असंयत आदतों के कारण हुई प्रतीत नहीं होती। मेरी (हमारी) राय में उसकी असमर्थता स्पष्टतः अनियमित या असंयत आदतों के कारण हुई है।</p>
(ख)	<p style="text-align: center;">"ख"</p> <p style="text-align: center;">(यदि और आगे सेवा के योग्य हो)</p> <p>मेरी (हमारी) राय यह है कि श्री ----- पुत्र श्री ----- उस सेवा से जो वह करता रहा है कम परिश्रम की सेवा और आगे करने के योग्य है या ----- मास तक विश्राम करने या समुचित उपचार के पश्चात और आगे सेवा करने के योग्य हो सकेगा।</p> <p>किसी कर्मचारी को, जो और आगे सेवा के लिए असमर्थता का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है यदि वह इयूटी पर हो तो उसको इयूटी से मुक्त करने की तारीख से सेवा से हटा दिया जायेगा, जिसकी व्यवस्था स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही बिना किसी विलंब के की जानी चाहिए, या यदि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के समय वह छुट्टी पर हो तो उसे उस छुट्टी की या बढ़ाई गई छुट्टी, यदि मंजूर की गई हो, की समाप्ति पर सेवा से हटा दिया जायेगा।</p>

- (3) इस विनियम में अन्तर्विष्ट उपबंधों की अध्यधीन रहते हुए उस कर्मचारी के मामले में, जो विकलांगता पेंशन पर सेवानिवृत्त होता है, विकलांगता पेंशन की रकम इन विनियमों के अधीन अनुज्ञेय परिवार पेंशन की रकम से कम नहीं होगी।

29. परिवार पेंशन (Family Pension) :

किसी ऐसे निगम कर्मचारी जो सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के पश्चात मर जाता है के परिवार को इन विनियमों के ऐसी दरों पर या ऐसे उपबंधों के अनुसार परिवार पेंशन का हकदार होगा, जो इन विनियमों में अंतरविष्ट है।

अध्याय-4**अर्हकारी (पेंशन योग्य) सेवा (Qualifying Service)****30. अर्हकारी पेंशन योग्य सेवा (Qualifying Service) का प्रारम्भ**

- (i) किसी निगम के कर्मचारी की सेवा तब तक पेंशन के लिए अर्हक नहीं होती जब तक कि वह अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ले।
- (ii) प्रत्येक कर्मचारी की सेवा तब प्रारंभ होती है जब वह उस पद का कार्यग्रहण करता है जिस पर वह निगम में पहली बार नियमित रूप से नियुक्त किया गया है।

31. अर्हता की शर्तें

किसी कर्मचारी की सेवा पेंशन के लिए तब तक अर्हक नहीं होती जब तक कि वह निम्नलिखित तीन शर्तों के अनुरूप न हो:-

प्रथम -सेवा निगम के अधीन अवश्य होनी चाहिए।

द्वितीय - नियोजन, निगम के स्टाफ विनियमों के अधीन अधिष्ठायी/स्थायी, अस्थायी या स्थापन्न हैसियत में हो।

तृतीय -सेवा के लिए निगम द्वारा संदाय किया जाये।

32. किसी सेवा को अर्हक सेवा के रूप में घोषित करने की निगम की शक्ति:

तथापि, निगम यह घोषित कर सकेगा कि कोई भी विनिर्दिष्ट सेवा या किसी कर्मचारी द्वारा की गयी सेवा, जो राज्य सरकार के नियमानुसार अनुमत हो, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिनको निगम अधिरोपित करना उचित समझे, पेंशन के लिए अर्हक होगी।

33. वे सेवाएं, जो पेंशन के लिए अर्हक होंगी:

निगम में किसी कर्मचारी द्वारा की गयी सेवाएं निम्नलिखित मामलों में पेंशन के लिए अर्हक होंगी:-

- (i) परिवीक्षाधीन व्यक्ति/प्रोबेशनर ट्रेनी (Probationer Trainee) द्वारा की गयी सेवा
- (ii) कर्मचारी द्वारा की गयी अस्थायी सेवा, परन्तु वह स्टाफ विनियम, 1958 की धारा 61 में अधिकथित समय वेतनमान के किसी पद पर भर्ती की प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किया गया हो
- (iii) (क) सेवा का वह समय या कालावधि, जो वेतन और भत्तों सहित छुट्टी पर व्यतीत की हो
(ख) असाधारण छुट्टी (बिना वेतन और भत्तों की छुट्टी) पर व्यतीत समय, जो नीचे उल्लेखित किन्हीं भी परिस्थितियों में ली गयी हो:-

- I. यदि वह किसी सरकारी चिकित्सालय के प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक या निगम द्वारा प्राधिकृत किसी भी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र पर ली गयी हो।

- II. यदि वह उच्चतर वैज्ञानिक या तकनीकी अध्ययन जारी रखने के लिए निगम की सम्यक पूर्व अनुज्ञा से ली गयी हो।
- III. यदि वह उपद्रव या प्राकृतिक विपदा के कारण इयूटी ग्रहण करने या पुनःग्रहण करने में कर्मचारी की असमर्थता के कारण ली गयी हो, बशर्ते कि उसके पास किसी भी प्रकार की कोई अन्य छुट्टी शेष न हो।
- IV. निगम की सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण (यात्रा समय सहित) पर व्यतीत समय, बशर्ते कि उसको निगम द्वारा प्रशिक्षण के कोर्स के लिए चयनित किया गया हो और भेजा गया हो।
- V. परसेवा में/सरकारी/स्वशासी निकायों में प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत समय सहित भारत में या भारत के बाहर इयूटी पर प्रतिनियुक्ति की कालावधि, परन्तु राज्य सरकार की अधीन समय समय पर प्रवृत्त दरों पर पेंशन अभिदान उधारगृहीता प्राधिकारी द्वारा सदत्त किया गया हो, और उसमें विफल रहने पर कर्मचारी स्वयं निगम को अभिदान का संदाय कर सकेगा।
- VI. निलम्बनाधीन व्यतीत किया गया समय पूरा गिना जायेगा, यदि जांच या विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर कर्मचारी को पूर्णतः विमुक्त या दोषमुक्त कर दिया गया हो या निलंबन को पूर्णतः अनुचित ठहरा दिया गया हो। अन्य मामलों में निलम्बन की कालावधि तब तक नहीं गिनी जायेगी जब तक कि विभागीय कार्यवाहियों की समाप्ति पर आदेश पारित करने वाला सक्षम प्राधिकारी उस समय अभिव्यक्त रूप से यह घोषित न कर दे कि वह उस सीमा तक, जो कि सक्षम प्राधिकारी घोषित करे, गिनी जायेगी।
- VII. ऐसा कर्मचारी जो निगम की सेवा से पदच्युत, हटाया या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाये किन्तु अपील या पुनरीक्षण पर बहाल कर दिया जाये, उसकी पिछली सेवा अर्हता सेवा के रूप में गिने जाने का हकदार होगा। पदच्युति, हटाये जाने या यथास्थिति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख और बहाल किये जाने की तारीख के बीच के सेवा-व्यवधान की कालावधि तब तक नहीं गिनी जायेगी जब तक कि उस प्राधिकारी द्वारा, जिसने बहाली के आदेश पारित किये हैं, विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा उक्त कालावधि को इयूटी के रूप में या देय और अनुज्ञेय छुट्टी मंजूर करके नियमित नहीं कर दिया जाये।

34. व्यवधानः

निम्नलिखित दशाओं के सिवाय, कर्मचारी की सेवा में हुए व्यवधान से उसकी पिछली सेवा समाप्त हो जाती है:-

- (क) प्राधिकृत अनुपस्थिति को छुट्टी के रूप में स्वीकार करना।
- (ख) अनुपस्थिति छुट्टी के क्रम में प्राधिकृत।
- (ग) निलंबन, जब कि निलंबित व्यक्ति को तुरन्त बहाल कर दिया जाये या अधिकारी मर जाये या सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात कर दिया जाये या निलंबनाधीन रहते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की

आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त कर दिया जाये एवं निलंबन अवधि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित नहीं किया गया हो।

(घ) स्थापन में कमी करने के कारण छंटनी करने पर पद की समाप्ति ।

(इ) लोक हित में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरण के मामले में निगम के विनियमों के अधीन अनुज्ञात या प्राधिकृत कार्यग्रहण काल।

टिप्पणी:

1. छुट्टी के उपरान्त अनुपस्थित रहने या बिना छुट्टी की अनुपस्थिति की कालावधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जाती है।
2. कार्यग्रहण-काल अर्हक नहीं होता है यदि उस कालावधि में कोई वेतन और भत्ते संदत्त नहीं किये जाते।
3. कोई कर्मचारी, जो निगम की सेवा से त्यागपत्र देता है या पदच्युत कर दिया जाता है तो उसकी पिछली सेवा नहीं गिनी जायेगी यदि उसको नयी नियुक्ति दे दी गयी है।
4. कोई प्राधिकारी, जो पेंशन मंजूर करता है, पिछली सेवा समपहरण को समाप्त करने के लिए उसके पूर्ण विवेकानुसार बिना छुट्टी की अनुपस्थिति की कालावधि को भूतलक्षी प्रभाव से भत्तों सहित छुट्टी में संगणित कर सकेगा।
5. यहां यह स्पष्ट करना समीचीन होगा कि निगम में प्रचलित स्टॉफ रेग्यूलेशन के अंतर्गत कर्मचारी को दण्डित किया जाता है एवं उसकी पूर्व की समस्त सेवायें समाप्त कर दी जाती हैं तो उसे कोई पेंशन एवं ग्रेच्युटी के लाभ देय नहीं होंगे।

अध्याय - 5

पेंशन की रकम (Amount of Pension)

35. परिलब्धियां (Emoluments) :

पेंशन, सेवा ग्रेच्युटी एवं सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त अभिव्यक्ति “परिलब्धियों से पद के समय-समय पर पूर्व में लागू पे-कमीशन के अनुसार वेतनमान पर मिल रहे वेतन, ग्रेड-पे, पे-मैट्रिक्स के लेवल में वेतन और विशेष वेतन, यदि कोई हो या योग अभिप्रेत है जो निगम कर्मचारी उसकी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व या उसकी मृत्यु की तारीख को प्राप्त कर रहा था या जिसका वह हकदार था। परन्तु विशेष वेतन को परिलब्धियों में सेवानिवृत्ति की तारीख से ठीक पूर्व गत 10 महिनो के औसत के आधार पर जो भी लाभप्रद हो सम्मिलित किया जायेगा।

परन्तु यह भी कि निगम कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु, यथास्थिति के समय तत्समय लागू वेतनमान के अनुसार वेतन, ग्रेड-पे, पे-मैट्रिक्स के लेवल में वेतन के योग पर अनुज्ञेय महंगाई भत्ते की रकम को सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी के प्रयोजनार्थ परिलब्धियों का भाग रूप समझा जायेगा।

नोट:-पे-मैट्रिक्स व्यवस्था लागू होने से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रकरण सेवानिवृत्ति पर देय यथा संशोधित वेतन/ग्रेड-पे व्यवस्था अनुसार निस्तारित किये जावेंगे।

36. भत्ते, जिनको नहीं गिना जाता (Allowances which don't count) :

पेंशन के अवधारण के लिए निम्नलिखित भत्तों को नहीं गिना जाता है –

1. परिक्षेत्र के खर्चीले होने के प्रतिफलस्वरूप मंजूर किये गये भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता, सर्दी भत्ता, पहाड़ी भत्ता आदि आदि।
2. यात्रा के खर्च की पूर्ति के लिए मंजूर किया गया यात्रा भत्ता या भत्ते,
3. गृह किराया भत्ता,
4. जीवन निर्वाह के खर्च की पूर्ति के लिए महंगाई भत्ता या प्रतिकर,
5. उच्चतर या विशेष अर्हताओं के लिये मंजूर किया गया वैयक्तिक भत्ता या वैयक्तिक वेतन,
6. समेकित वेतन या पारिश्रमिक।

37. पेंशन रकम कैसे विनियमित की जायेगी (How to regulate the pension amount) :

1. पेंशन की रकम अर्हक सेवा काल द्वारा अवधारित की जायेगी, जैसा कि विनियम में दिया गया है। किसी कर्मचारी को अनुज्ञेय पेंशन की संगणना के प्रयोजनार्थ, वर्ष के 6 माह या इससे अधिक के बराबर के भाग को सेवा के छः मास की संपूरित कालावधि के रूप में माना जायेगा। अर्हक सेवा की संगणना करने में आधे दिन के भाग को अगला पूरा दिन मानकर गिना जायेगा।
2. किसी ऐसे कर्मचारी के मामले में जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी इन विनियमों के अधीन पेंशन में कमी करने का आदेश देता है, कमी पूरे रुपये में की जायेगी ताकि कमी करने के पश्चात परिणामिक पेंशन पूरे रूपों में संदत्त की जा सके।
3. विनियमों के उपबंधों के अनुसार संगणित या अवधारित पेंशन की रकम पूरे रुपये में होगी।

38. पूर्ण पेंशन केवल अनुमोदित सेवा के लिए ही अनुज्ञेय है (Full Pension admissible for approved service only) :

1. इन विनियमों के अधीन अनुज्ञेय पूर्ण पेंशन सामान्य अनुक्रम के रूप में मंजूर नहीं की जानी है जब तक कि, की गई सेवा को पूर्ण पेंशन हेतु मंजूरकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाये।
2. यदि किसी कर्मचारी द्वारा उक्त-विनियम (1) के अधीन की गई सेवा संतोषप्रद नहीं रही है तो पेंशन मंजूरकर्ता प्राधिकारी आदेश द्वारा पेंशन या उपदान, या दोनों की रकम में उतनी कमी कर सकेगा जो वह प्राधिकारी उचित समझे।
3.
 - (i) पेंशन में कमी करने के बारे में कोई आदेश, जैसा कि उक्त-विनियम (2) में परिकल्पित है, जब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कर्मचारी को मामले में अभ्यावेदन करने का युक्ति संगत अवसर नहीं दिया गया हो।
 - (ii) पहले ही मंजूर की जा चुकी पेंशन में, पेंशनर की सेवा पूर्णतः संतोषप्रद नहीं रहने के किसी ऐसे सबूत की दशा में, जो पेंशन मंजूर करते समय उपलब्ध नहीं था, कमी नहीं की जायेगी।

4. जब कभी भी किसी कर्मचारी की पेंशन में कमी करने वाला आदेश पारित किया जाये, प्रभावित कर्मचारी को ऐसे प्राधिकारी को अपील करने का अधिकार होगा जिसको पदच्युति या हटाये जाने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील होती है।
39. पेंशन किसी ऐसे कर्मचारी को अनुज्ञेय नहीं है जिसने सेवा की 20 संपूरक छः मासिक कालावधियों से कम कालावधि पूरी की हो।

अनुभाग –(II)

पेंशन और उपदान की रकम का अवधारण

(DETERMINATION OF AMOUNT OF PENSION AND GRATUITY)

40. 15 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary retirement after completion of 15 years of qualifying service) :

किसी निगम कर्मचारी ने जब 15 वर्षों की अर्हकारी सेवा पूरी करली हो तो उसके बाद किसी भी समय वह नियुक्ति प्राधिकारी को न्यूनतम 3 माह का लिखित नोटिस देकर सेवानिवृत्त हो सकेगा। परन्तु इस प्रकार की सेवानिवृत्ति के नोटिस पर नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी। परन्तु यह कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी उक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए अनुमति देने से मना नहीं करता है तो उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से वह सेवानिवृत्ति स्वतः प्रभावी हो जायेगी।

41. 15 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory retirement after completion of 15 years of qualifying service):

- (i) किसी निगम कर्मचारी के द्वारा 15 वर्षों की अर्हकारी सेवा पूरी कर लेने या 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, जो भी इनमें से पहले हो, किसी भी समय, नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से अपना समाधान कर लेने पर कि संबंधित निगम कर्मचारी ने अपनी अकर्मण्यता या संदेहास्पद सत्यनिष्ठा या कार्यालयीय कर्तव्यों के निर्वहन में अक्षमता या कार्यालयीय कर्तव्यों के उचित निष्पादन में अकुशलता के कारण अपनी उपयोगिता नष्ट कर दी है, संबंधित निगम कर्मचारी को विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात निगम हित में सेवानिवृत्त होने के लिए लिखित में कह सकेगा। ऐसी सेवानिवृत्ति के मामले में निगम कर्मचारी सेवानिवृत्ति पेंशन के लिए हकदार होगा।
- (ii) ऐसे मामले में नियुक्ति प्राधिकारी निगम कर्मचारी को जिस तारीख को उसे निगम हित में सेवानिवृत्त होने के लिए लिखित में कहा जायेगा उससे न्यूनतम 3 माह पूर्व लिखित नोटिस देगा या उस नोटिस के बदले में उसे 3 माह के वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जायेगा।
- (iii) ऐसे मामले में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारी 30 दिन की कालावधि के भीतर सेवानिवृत्ति के आदेश के विरुद्ध राजस्थान वित्त निगम निदेशक मण्डल के डायरेक्टर्स (Board of Directors) को अभ्यावेदन कर सकेगा। यदि उसके अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद किसी समय पूर्व सेवानिवृत्त निगम कर्मचारी को बहाल किये जाने का विनिश्चय किया जाता है तो प्राधिकारी

समय पूर्व सेवानिवृत्ति की तारीख और बहाली या यथास्थिति, अधिवर्षिता की आयु की तारीख के बीच की कालावधि के बारे में आदेश करेगा।

क - पेंशन की राशि
(Amount of Pension):

42. पेंशन की राशि (Amount of Pension) :

अधिवाषिकी, सेवानिवृत्ति, अक्षमता (Disability) तथा क्षतिपूरक पेंशन एवं सेवा ग्रेच्युटी की राशि निम्न प्रकार होगी:-

- (i) यदि निगम कर्मचारी 10 वर्षों की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पहले ही इन विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत सेवानिवृत्त हो रहा हो तो सेवा ग्रेच्युटी (Service Gratuity) राशि अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण 6 माह की अवधि के लिए आधे माह की परिलब्धियों की दर से संगणित (Calculate) की जायेगी।
- (ii) यदि निगम कर्मचारी कम से कम 28 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने के बाद इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार पेंशन की राशि की संगणना परिलब्धियों की परिभाषा के अनुसार, निगम में कर्मचारी को उसकी वेतन श्रृंखला में उच्चतम वेतन के 50 प्रतिशत के अधिकतम अध्यधीन रहते हुए, परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर पर की जायेगी जिन्हें निगम कर्मचारी सेवानिवृत्ति की तारीख से ठीक पूर्व प्राप्त कर रहा था।
- (iii) यदि निगम कर्मचारी 28 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पहले परन्तु 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने के बाद इन विनियमों के प्रावधान के अनुसार सेवानिवृत्त हो रहा है, तो पेंशन की राशि उपरोक्त (ii) के अधीन स्वीकार्य पेंशन राशि कर्मचारी के द्वारा सम्पादित अर्हक सेवा के अनुपात में (आनुपातिक पेंशन) देय होगी तथा किसी भी दशा में पेंशन की राशि 8850/-रु. या राज्य सरकार में निर्धारित न्यूनतम मासिक पेंशन राशि से कम नहीं होगी।
- (iv) ऊपर उल्लेखित किसी बात के होते हुए भी असमर्थता पेंशन की राशि स्वीकार्य परिवार पेंशन की राशि से कम नहीं होगी।
- (v) अर्हकारी सेवा की अवधि को गिनने में तीन माह के बराबर या अधिक के वर्ष के भिन्नांश को पूर्ण आधे वर्ष के रूप में माना जायेगा तथा उसे अर्हकारी सेवा के रूप में गिना जायेगा।
- (vi) उपरोक्तानुसार अंतिम रूप से अवधारित पेंशन की राशि पूर्ण रूपों में अभिव्यक्त की जायेगी तथा जहां पेंशन में रुपये का भिन्नांश आता हो वहां उसे अगले रुपये में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

43. अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि :

पुराने वयोवृद्ध पेंशनर्स/फैमिली पेंशनर्स के 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें प्राप्त पेंशन/ फैमिली पेंशन में निम्न प्रकार अंकित अतिरिक्त लाभ दिया जायेगा –

पेंशनर/फैमिली पेंशन की आयु	: पेंशन/फैमिली पेंशन राशि पर अतिरिक्त लाभ
80 वर्ष किन्तु 85 वर्ष से कम	: मूल पेंशन/फैमिली पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष किन्तु 90 वर्ष से कम	: मूल पेंशन/फैमिली पेंशन का 30 प्रतिशत
90 वर्ष किन्तु 95 वर्ष से कम	: मूल पेंशन/फैमिली पेंशन का 40 प्रतिशत
95 वर्ष किन्तु 100 वर्ष से कम	: मूल पेंशन/फैमिली पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वर्ष या अधिक	: मूल पेंशन/फैमिली पेंशन का 100 प्रतिशत

पेंशन स्वीकार करने वाले प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अब से जारी किये जाने वाले पेंशन भुगतान आदेशों में और परिवार के विवरण संबंधी प्रारूप में सदैव पेंशनर का जन्म दिनांक तथा सेवानिवृत्ति/मृत्यु के दिन आयु का उल्लेख किया गया है। ताकि देय होने पर अतिरिक्त पेंशन/फैमिली पेंशन का भुगतान पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा शीघ्र करने में सुविधा रहे। पेंशन भुगतान आदेशों में पेंशन/फैमिली पेंशन की अतिरिक्त राशि का भी पृथक से स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा। उदाहरण के रूप में जहां किसी 80 वर्ष से अधिक के पेंशनर/फैमिली पेंशनर की पेंशन/फैमिली पेंशन 10,000/-रु. मासिक है तो (i) मूल पेंशन/फैमिली पेंशन = 10,000/- रु. तथा (ii) 80 वर्ष का होने पर अतिरिक्त लाभ = 2,000/- रु. जब वह 85 वर्ष का हो जावे तो (i) मूल पेंशन/फैमिली पेंशन = 10,000/- रु. तथा (ii) अतिरिक्त पेंशन = 3,000/- रु. अंकित किया जायेगा।

ख -सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी (Death / Retirement Gratuity):

44. सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी (Death / Retirement Gratuity)

- (i) (क) ऐसे निगम कर्मचारी जिसने 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करली हो तथा जो उक्त विनियम के अधीन ग्रेच्युटी या पेंशन के लिए पात्र हो चुका है, सेवानिवृत्त होने पर अर्हकारी सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 माह के लिए उसकी परिलब्धियों की एक चौथाई के बराबर सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी स्वीकार की जायेगी किन्तु यह परिलब्धियों से 16.5 गुणा की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहेगी।

- (ख) यदि निगम कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को इन विनियमों में उल्लेखित प्रक्रिया से नीचे तालिका में दी गई दरों पर मृत्यु ग्रेच्युटी का भुगतान किया जायेगा-

(I)	एक वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने से पूर्व	:	मासिक परिलब्धियों का दुगुना
(II)	एक वर्ष की अर्हक सेवा करने के पश्चात किन्तु 5 वर्ष की अर्हक सेवा से पूर्व	:	मासिक परिलब्धियों का छह गुना
(III)	5 वर्ष या अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम	:	मासिक परिलब्धियों का 12 गुना
(IV)	11 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	:	मासिक परिलब्धियों का 20 गुना
(V)	20 वर्ष से अधिक	:	अर्हक सेवा की प्रत्येक पूर्ण की गई छह मासिक कालावधि के लिए, परिलब्धियों के आधा माह किन्तु परिलब्धियों के 33 गुना के अध्यधीन रहते हुए

परन्तु यह कि इस विनियम के अधीन संदेय सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी या मृत्यु ग्रेच्युटी की राशि 20 लाख रुपये (समय-समय पर यथा संशोधित) से अधिक की नहीं होगी। परन्तु यह कि जहां

अंतिम रूप से संगणित सेवानिवृत्ति या मृत्यु ग्रेच्युटी की राशि में रुपये की भिन्न हो तो उसे अगले उच्चतर रुपये में बदल दिया जायेगा।

- (ii) कोई निगम कर्मचारी जो सेवा ग्रेच्युटी या पेंशन के लिए पात्र हो गया है यदि सेवा से निवृत्त होने जिसमें शास्ति के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी सम्मिलित है, की तारीख से पांच वर्ष के भीतर मर जाता है तथा अपने मृत्यु के समय ऐसी ग्रेच्युटी या पेंशन के कारण उप-विनियम (i) के अधीन स्वीकार्य सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के साथ उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त की गई राशियां तथा उसके द्वारा रूपांतरित करवाये गये पेंशन के किसी हिस्से की राशि उसकी परिलब्धियों के 12 गुणा से कम है, तो उस कमी के बराबर की अवशिष्ट ग्रेच्युटी उसके परिवार को विनियम में वर्णित तरीके के अनुसार स्वीकृत की जा सकेगी।
- (iii) इन विनियमों के अधीन स्वीकार्य परिलब्धियां विनियम 35 के अनुसार गिनी जायेंगी।
- (iv) इस विनियम के प्रयोजनों के लिए निगम कर्मचारी के संबंध में परिवार से निम्नलिखित अभिप्रेत है -
- (क) पुरुष कर्मचारियों के मामलों में पत्नि या पत्नियां, महिला कर्मचारियों के मामलों में पति,
 - (ख) पुत्र जिसमें गोद लिये गये पुत्र तथा सौतेले पुत्र भी सम्मिलित हैं
 - (ग) अविवाहित पुत्रियां जिनमें सौतेली पुत्रियां एवं गोद ली गई पुत्रियां भी सम्मिलित हैं
 - (घ) विधवा पुत्रियां जिनमें सौतेली पुत्रियां एवं गोद ली गई पुत्रियां भी सम्मिलित हैं
 - (ङ) पिता जिसमें उन व्यक्तियों के मामले में जिनके पैतृक कानून गोद की अनुमति देते हैं, गोद लिये गये पिता भी सम्मिलित हैं। (including adoptive parents in the case of individuals whose personal law permits adoption)
 - (च) माता जिसमें उन व्यक्तियों के मामले में जिनके पैतृक कानून गोद की अनुमति देते हैं, गोद लिये गये माता भी सम्मिलित हैं। (including adoptive parents in the case of individuals whose personal law permits adoption)
 - (छ) 18 वर्ष से कम आयु के भाई जिसमें सौतेले भाई भी सम्मिलित हैं
 - (ज) अविवाहित बहिनें एवं विधवा बहिनें जिनमें सौतेली बहिनें भी सम्मिलित हैं
 - (झ) विवाहित पुत्रियां
 - (ञ) पूर्व मृत पुत्र के बच्चे
45. (i) (क) इन विनियमों के अधीन संदेय ग्रेच्युटी का भुगतान उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को किया जायेगा जिन्हें ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकार इन विनियमों में वर्णित नाम निर्देशन द्वारा प्रदत्त किया गया है।
- (ख) यदि ऐसा कोई नाम निर्देशन नहीं किया हो या यदि किया गया नाम निर्देशन अस्तित्व में नहीं रहता है तो ग्रेच्युटी का भुगतान नीचे दिये गये तरीके से किया जायेगा -
- (1) विनियम 44 के खण्ड (iv) के (क), (ख), (ग) एवं (घ) के अनुसार परिवार के जीवित सदस्य एक या अधिक हैं तो समस्त ऐसे सदस्यों को समान हिस्सों में।
 - (2) यदि उपरोक्त उपखण्ड-1 के अनुसार परिवार के सदस्यों में से कोई भी इस प्रकार जीवित न रहे लेकिन विनियम 53 के उप विनियम (iv) के खण्ड-

(ड),(च),(छ),(ज),(झ) एवं (ञ) के अनुसार एक या अधिक सदस्य हो तो ऐसे सभी सदस्यों को बराबर के हिस्से में।

- (ii) यदि निगम कर्मचारी विनियम के अंतर्गत स्वीकार ग्रेच्युटी को प्राप्त किये बिना मर जाता है तो ग्रेच्युटी का वितरण परिवार में उक्त विनियम (i) में निर्दिष्ट तरीके अनुसार किया जायेगा।
- (ii) यदि निगम कर्मचारी सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद मर जाता है तो परिवार की महिला सदस्य या कर्मचारी के भाई की ग्रेच्युटी में से हिस्सा पाने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यदि कर्मचारी की मृत्यु के बाद या ग्रेच्युटी में से उसका हिस्सा प्राप्त करने से पूर्व महिला सदस्य विवाह करती है या पुनर्विवाह करती है या भाई 18 वर्ष का हो जाता है।
- (iv) यदि निगम कर्मचारी के अवयस्क सदस्य को उपरोक्त विनियम के अधीन ग्रेच्युटी स्वीकार की जाती है तो उसका भुगतान उस अवयस्क के लिए उसके संरक्षक को किया जायेगा।

46. व्यक्ति जिन्हें ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा सकेगा:

- (1) (क) विनियम के अधीन संदेय ग्रेच्युटी का भुगतान उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को किया जायेगा जिन्हें ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकार, विनियम के अधीन नाम-निर्देशन के द्वारा, प्रदत्त किया गया है।
- (ख) यदि ऐसा कोई नाम-निर्देशन नहीं हो या यदि किया गया नाम-निर्देशन अस्तित्व में नहीं रहता है तो, ग्रेच्युटी का भुगतान नीचे दिये गये तरीकों से किया जायेगा –
 - (i) यदि उपरोक्त विनियम 44 के (4) के खण्ड (क), (ख), (ग) एवं (घ) के अनुसार परिवार के जीवित सदस्य एक या अधिक हैं तो समस्त ऐसे सदस्यों को समान हिस्सों में ;
 - (ii) यदि उपरोक्त विनियम के खण्ड (i) के अनुसार परिवार के हिस्सों में से कोई भी इस प्रकार जीवित न रहे, लेकिन विनियम 44 के उप विनियम (4) के खण्ड (ड),(च), (छ), (ज), (झ), (ञ) के अनुसार एक या अधिक सदस्य हों तो ऐसे सभी सदस्यों को बराबर के हिस्सों में।
- (2) यदि निगम कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद उपरोक्त विनियम 44 के (1) के अंतर्गत स्वीकार्य ग्रेच्युटी को प्राप्त किये बिना मर जाता है, तो ग्रेच्युटी का वितरण परिवार में उपरोक्त विनियम (1) में निर्दिष्ट तरीके के अनुसार किया जाएगा।
- (3) यदि निगम कर्मचारी सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद मर जाता है, तो परिवार की महिला सदस्य या मृतकर्मचारी के भाई के ग्रेच्युटी में से हिस्सा पाने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि निगम कर्मचारी की मृत्यु के बाद या ग्रेच्युटी में से उसका हिस्सा प्राप्त करने से पूर्व महिला सदस्य विवाह करती है या पुनर्विवाह करती है या भाई 18 वर्ष का हो जाता है।
- (4) जहां मृतक निगम कर्मचारी के परिवार के अवयस्क सदस्य को उपरोक्त विनियम 44 के अधीन ग्रेच्युटी स्वीकार की जाती है तो उसका भुगतान उस अवयस्क के लिए उसके संरक्षक को किया जाएगा।

47. ग्रेच्युटी प्राप्त करने से किसी व्यक्ति को विवर्जित (debar) करना :

- (i) यदि ऐसे किसी व्यक्ति पर जो निगम कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उपरोक्त विनियमों के अनुसार ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए पात्र है, कर्मचारी की हत्या करने का अपराध अथवा ऐसा अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित करने का आरोप लगाया जाता है तो ग्रेच्युटी में से अपना हिस्सा प्राप्त करने का उसका क्लेम निलंबित रहेगा, जब तक की उसके विरुद्ध प्रारंभ की गई दाण्डिक कार्यवाही का निष्कर्ष न निकल जाये।
- (ii) यदि उपरोक्त वर्णित दाण्डिक कार्यवाही के निष्कर्ष पर संबंधित व्यक्ति उसकी हत्या करने या हत्या करने हेतु दुष्प्रेरित करने का दोषी सिद्ध किया जाता है तो वह ग्रेच्युटी में से अपना हिस्सा प्राप्त करने से विवर्जित कर दिया जायेगा तथा वह राशि परिवार के अन्य पात्र सदस्यों को, यदि कोई हों, संदेय होगी।
- (iii) यदि उपरोक्त में वर्णित दाण्डिक कार्यवाही के निष्कर्ष पर संबंधित व्यक्ति हत्या करने या उसकी हत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप से दोषमुक्त हो जाता है तो, ग्रेच्युटी में से उसके हिस्से का उसको भुगतान किया जा सकेगा।
- (iv) उपरोक्त उप विनियम (i) (ii) के प्रावधान विनियम-44 में वर्णित अवितरित ग्रेच्युटी पर भी लागू होंगे।

48. सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी का व्यपगत होना (Lapse of retirement gratuity/death gratuity) :

जहां निगम कर्मचारी सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त किये बिना मर जाता है तथा अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ता है, तथा उसने कोई नाम निर्देशन नहीं किया है या उसके द्वारा किया गया नाम निर्देशन अस्तित्व में नहीं रहता है तो विनियमों के अंतर्गत ऐसे निगम कर्मचारी के संबंध में देय सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी की राशि निगम के पेंशन फण्ड में चली जायेगी।

49. नाम-निर्देशन (Nominations) :

- (i) निगम कर्मचारी, किसी सेवा में या पद पर अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति पर, विहित प्रारूप में जैसी भी स्थिति हो, एक नाम-निर्देशन करेगा, जिसमें एक या अधिक व्यक्तियों को विहित विनियम के अधीन देय सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी प्राप्त करने के अधिकार प्रदत्त करेगा। परन्तु यदि नाम-निर्देशन करते समय निगम कर्मचारी का परिवार हो, तो नाम-निर्देशन उसके परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के पक्ष में नहीं किया जायेगा। परन्तु यदि निगम कर्मचारी का परिवार न हो तो नाम-निर्देशन किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के पक्ष में या व्यष्टियों के निकाय (A body of individuals), जो चाहे निगमित (incorporated) हो अथवा नहीं, के पक्ष में किया जा सकेगा।
- (ii) यदि कोई निगम कर्मचारी उपरोक्त वर्णित उप-विनियम के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को नाम-निर्देशन करता है, तो वह उस नाम निर्देशन में नाम-निर्देशितियों में से प्रत्येक को देय हिस्से की राशि का विनिर्देश ऐसे तरीके से करेगा कि उसके अंतर्गत ग्रेच्युटी की सम्पूर्ण राशि आ सके।
- (iii) निगम कर्मचारी नाम-निर्देशन-पत्र में यदि विनिर्दिष्ट नाम-निर्देशितियों में से किसी की राजस्थान वित्त निगम कर्मचारी से पहले मृत्यु हो जाती है या जो निगम कर्मचारी की मृत्यु के

बाद किन्तु ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त करने से पहले मर जाता है तो उस नाम-निर्देशिति को प्रदत्त अधिकार ऐसे व्यक्ति को चला जायेगा जो उस नाम- निर्देशन-पत्र में विनिर्दिष्ट किया जाये परन्तु यदि नाम निर्देशन करते समय निगम कर्मचारी के परिवार में एक या अधिक सदस्य हों तो उक्त प्रकार से विनिर्दिष्ट व्यक्ति उसके परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य कोई नहीं होगा परन्तु यदि निगम कर्मचारी के परिवार में केवल एक सदस्य है, तथा नाम निर्देशन उसके पक्ष में किया गया है तो निगम कर्मचारी किसी भी व्यक्ति के पक्ष में या व्यष्टियों के निकाय, जो चाहे निगमित हो अथवा नहीं, के पक्ष में वैकल्पिक नाम-निर्देशिति या नाम-निर्देशितियों को नाम-निर्दिष्ट कर सकेगा:-

- (iv) यदि किसी ऐसे कर्मचारी, जिसका नाम-निर्देशन करने के समय कोई परिवार न हो, द्वारा किया गया नाम-निर्देशन या जहां उसके परिवार में केवल एक सदस्य हो वहां उपरोक्त वर्णित विनियम के अधीन निगम कर्मचारी द्वारा किया गया नाम-निर्देशन, निगम कर्मचारी का बाद में परिवार होने पर या उसके परिवार में अतिरिक्त सदस्यों के होने पर, जैसी भी स्थिति हो, अवैद्य (invalid) हो जायेगा।
- (v) निगम कर्मचारी, किसी भी समय, नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित नोटिस भेजकर किसी भी नाम-निर्देशन को रद्द/संशोधित कर सकेगा।

ग - परिवार पेंशन विनियम (Family Pension Regulation)

50. लागू होना (Applicability) :

इन विनियमों के प्रावधान विनियम लागू होने की दिनांक से प्रभावी होंगे तथा उक्त विनियम पेंशनर्स/कर्मचारी के परिवार पर लागू होंगे। परन्तु ये विनियम उन पर लागू नहीं होंगे:-

- (क) जिन्हें आकस्मिक निधि से भुगतान किया जाता है,
- (ख) वर्कचार्ज स्टाफ,
- (ग) नैमित्तिक मजदूर (Casual Labour),
- (घ) संविदा पर नियुक्त किये गये व्यक्ति (Persons appointed on contract)
- (ङ) जो पेंशनर्स पूर्व में लागू पेंशन विनियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं
- (च) ऐसे अस्थायी कर्मचारी, जो राजस्थान वित्त निगम स्टाफ विनियमों में अधिकथित भर्ती की प्रक्रिया अनुसरण किये बिना तदर्थ आधार पर नियोजित किये जाये।

51. पेंशन की स्वीकार्यता (Admissibility of Pension) :

विनियमों में निर्दिष्ट दरों पर पारिवारिक पेंशन इन विनियमों के अंतर्गत निगम पेंशनर्स/कर्मचारी के परिवार को स्वीकृत की जायेगी जो दिनांक 01.04.2023 एवं उसके बाद:

- (क) सेवा से निवृत्ति के बाद कर्मचारी/पेंशनर मर जाता है।
- (ख) सेवा में रहते हुए, एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने पर मर जाता है परन्तु स्थाई पदों के विरुद्ध प्रोबेशनरों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों पर यह एक वर्ष की सेवा की शर्त लागू नहीं होगी।

52. परिवार पेंशन की राशि (Amount of Family Pension) :**1. इस अध्याय के अधीन अनुज्ञेय परिवार पेंशन की रकम निम्न प्रकार होगी:-**

- (i) पारिवारिक पेंशन, 8850/-रु. अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिमास के न्यूनतम और सरकार में उच्चतम वेतन (सरकार में उच्चतम वेतन 01.01.2016 से 2,18,600/-रु. है) के 30 प्रतिशत के अधिकतम के अध्याधीन रहते हुये कर्मचारी की वास्तविक परिलब्धियों की 30 प्रतिशत अनुज्ञेय होगी।
- (ii) (क) जहां कोई निगम कर्मचारी, जिस पर समय-समय पर यथा- संशोधित कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 लागू नहीं होता है, अपनी आयु से पूर्व कम से कम 7 वर्ष की सतत् सेवा कर चुकने के बाद सेवा में रहते हुये मर जाता है, तो अंतिम रूप से आहरित परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर पर या उपरोक्त विनियम (i) के अधीन स्वीकार्य परिवार पेंशन की राशि से दुगुनी, जो भी कम हो, दर से परिवार पेंशन स्वीकार की जाएगी।

(ख) जहां कोई निगम कर्मचारी, जो समय-समय पर यथा- संशोधित कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 द्वारा शासित होता है, अपनी मृत्यु से पूर्व कम से कम 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुकने के बाद सेवा में रहते हुये मर जाता है, तो उस निगम कर्मचारी का परिवार भी अंतिम रूप में आहरित परिलब्धियों की 50 प्रतिशत की दर पर या उपरोक्त विनियम (i) के अधीन स्वीकार्य परिवार पेंशन के डेढ़ गुने के बराबर, जो भी कम हो, परिवार पेंशन के लिए हकदार होगा।

परन्तु यह कि जहां पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन निगम कर्मचारी को क्षतिपूरक (Compensation) का भुगतान नहीं किया जाता, वहां पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी को एक प्रमाण पत्र इस आशय का भेजेगा कि मृतक निगम कर्मचारी का परिवार पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन किसी क्षतिपूरक को प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है तथा उस मामले में उस निगम कर्मचारी का परिवार उपरोक्त विनियम (ii) (क) में यथा-स्वीकार्य परिवार पेंशन के लिए हकदार होगा।

- (iii) उन निगम कर्मचारियों के संबंध में, जो 01.10.1996 को या उसके बाद सेवा में रहते हुए मर गये या मर जाते हैं, उपरोक्त विनियम (ii) के अधीन बढी हुई दर पर परिवार पेंशन की राशि का भुगतान निम्न प्रकार किया जायेगा-

(क) सेवा में रहते हुए निगम कर्मचारी की मृत्यु होने पर, मृत्यु की तारीख के बाद 7 वर्ष की अवधि तक या उस तारीख तक, जिसको कि मृत निगम कर्मचारी यदि जीवित रहता है (67 वर्ष की आयु) प्राप्त कर लेता, इनमें से जो भी अवधि कम हो, उस तक, परिवार पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

(ख) सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने पर, उपरोक्त विनियम (ii) में वर्णित बढी हुई दरों पर परिवार पेंशन का भुगतान उस तारीख तक जिसको कि मृत निगम कर्मचारी यदि जीवित रहता तो (67 वर्ष की आयु) प्राप्त कर लेता या 7 वर्ष तक, इनमें से जो भी कम हो, उस तक किया जायेगा, किन्तु किसी भी स्थिति में परिवार पेंशन की राशि, निगम कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय उसे स्वीकृत की गई पेंशन से अधिक नहीं होगी। तथापि, उन मामलों में, जहां उपरोक्त विनियम (i) के अधीन स्वीकार्य परिवार पेंशन की राशि,

सेवानिवृत्ति के समय स्वीकृत की गई पेंशन से अधिक है, तो इस खण्ड के अधीन स्वीकृत की गई परिवार पेंशन की राशि वह होगी जो उपरोक्त विनियम (i) के अधीन परिवार पेंशन के रूप में स्वीकृत की गई है। सेवानिवृत्ति के समय स्वीकृत पेंशन उसके उस भाग को सम्मिलित करते हुए होगी जिसे सेवानिवृत्त निगम कर्मचारी ने मृत्यु से पूर्व रूपांतरित (Commuted) करा लिया था। एवं

(ग) उपरोक्त विनियम(क) एवं (ख) में वर्णित अवधि की समाप्ति के बाद उपरोक्त विनियम (i) में दी गई दरों पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

(iv) उपरोक्त विनियम (ii) और (iii) में किसी बात के होने पर भी, माता-पिता के मामले में परिवार पेंशन की रकम उपरोक्त विनियम (i) में यथा-अनुज्ञेय होगी।

2. जहां कोई निगम कर्मचारी उसकी मृत्यु के पूर्व 7 वर्ष से अन्यून की निरन्तर सेवा करके सेवा में रहते हुए मर जाता है, तो संदेय पेंशन निम्न प्रकार होगी:-

(क) मृत्यु होने की तारीख की अगली तारीख से 7 वर्ष की कालावधि के लिए या उस तारीख तक जिसको, कर्मचारी यदि जीवित रहता तो अधिवार्षिकी की सामान्य आयु तक पहुंच जाता, जो भी कालावधि कम हो, संदेय पेंशन की रकम, अंतिम आहरित वेतन की 50 प्रतिशत या ऊपर उप-विनियम(1) के अधीन की परिवार पेंशन की रकम की दुगुनी जो भी कम हो होगी।

(ख) उसके पश्चात संदेय परिवार पेंशन इस विनियम से उप-विनियम(1) में अधिकथित दरों पर होगी।

3. जहां 7 वर्ष अन्यून की निरन्तर सेवा कर चुकने वाला कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के पश्चात मर जाता है तो संदेय परिवार पेंशन की रकम निम्न प्रकार होगी -

(क) 7 वर्ष की कालावधि के लिए या उस तारीख तक जिसको वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करता, जो भी पहले हो, परिवार पेंशन की रकम अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत या इस विनियम के उप-विनियम(1) के अधीन की परिवार पेंशन की रकम की दुगुनी, जो भी कम हो, होगी।

(ख) उसके पश्चात परिवार पेंशन उप-विनियम (1) में अधिकथित दर पर होगी, परन्तु परिवार पेंशन की रकम सेवानिवृत्ति के समय मंजूर की गई मूल पेंशन की रकम से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी।

53. (i) इस अध्याय के प्रयोजनार्थ परिवार में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

(क) पुरुष कर्मचारी की दशा में पत्नी तथा महिला कर्मचारी की दशा में पति,

(ख) न्यायिक रूप से पृथक किये गये पत्नि या पति, ऐसा पृथक्करण जारकर्म के आधार पर स्वीकृत नहीं किया गया हो (judicially seprated wife or husband, such sepration not being granted on the ground of adultery);

(ग) अविवाहित पुत्र उसके 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने या 9500/-रूपये से अधिक की मासिक आय अर्जित करने तक, जो भी पहले हो ;

(घ) अविवाहित पुत्री उसके विवाह की तारीख या 9500/-रूपये से अधिक की मासिक आय उपार्जित करना प्रारम्भ करने तक, जो भी पहले हो ;

- (ड) किसी भी आयु की विधवा/तलाकशुदा पुत्री, उसके पुनर्विवाह करने की तारीख या 9500/-रूपये से अधिक की मासिक आय उपार्जित करना प्रारम्भ करने तक, जो भी पहले हो ;
- (च) माता/पिता, जो निगम कर्मचारी पर तब पूर्णतया आश्रित थे जब वह जीवित था, परन्तु यह तब तक ही जब कि मृतक कर्मचारी के पीछे न तो कोई विधवा रही हो और न ही कोई संतान और माता-पिता की आय 9500/-रूपये प्रतिमाह से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजनार्थ पुत्र/पुत्री में निगम कर्मचारी का वैद्य रूप से गोद लिया गया पुत्र/पुत्री और मृत्यु के पश्चात जन्मी संतान भी सम्मिलित है।

- (ii) इस अध्याय के प्रयोजनार्थ परिलब्धियां (Emoluments) ; वे परिलब्धियां अभिप्रेत हैं जिन्हें मृतक निगम कर्मचारी सेवा में रहते हुए अपनी मृत्यु की तारीख को या अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व प्राप्त कर रहा था, जहां सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु की तारीख को या सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व ऐसा निगम कर्मचारी अवकाश (असाधारण अवकाश सहित) पर अनुपस्थित था या निलंबित था, वहां पर परिलब्धियों का अभिप्राय उन परिलब्धियों से है जिसे उसने ऐसे अवकाश पर प्रस्थान करने या निलंबित होने के ठीक पूर्व प्राप्त किया था।

54. परिवार पेंशन स्वीकृत करने की शर्त (Condition of Grant) :

परिवार पेंशन निम्नलिखित को स्वीकृत की जायेगी -

- (क) विधवा/विधुर को, मृत्यु या पुनर्विवाह करने की तारीख तक, जो भी पहले हो।
- (ख) अव्यस्क पुत्र, उसके पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त करने या 9500/-रु. से अधिक की मासिक आय उपार्जित करने तक, जो भी पहले हो।
- (ग) अव्यस्क पुत्री, उसके विवाह की तारीख तक या 9500/-रु. से अधिक की मासिक आय उपार्जित करने तक, जो भी पहले हो।
- (घ) किसी भी आयु की विधवा/तलाकशुदा पुत्री उसके पुनर्विवाह की तारीख तक या उस तारीख तक जिसको वह 9500/-रु. से अधिक की मासिक आय उपार्जित करना प्रारम्भ करती है या मृत्यु की तारीख तक।
- (ड) माता-पिता जो निगम कर्मचारी पर तब पूर्णतया आश्रित थे जब वह जीवित था/थी, बशर्ते कि मृतक कर्मचारी के पीछे न तो विधवा रही हो न ही कोई संतान और माता-पिता की आय 9500/-रु. मासिक आय से अधिक न हो।

परन्तु यह कि यदि निगम कर्मचारी/पेंशनर का किसी भी आयु का पुत्र या पुत्री किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से पीड़ित हो या शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त या अंधा या बहरा या गूंगा हो जिससे वह जीविका अर्जित करने में असमर्थ हो जाये तो ऐसे पुत्र या पुत्री को परिवार पेंशन जीवन भर के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुए, भुगतान की जायेगी, अर्थात्

- (i) यदि ऐसी संतानें एक से अधिक हो जो मानसिक विकार या निःशक्तता से पीड़ित हो या जो शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त या अंधा या बहरा या गूंगा हों तो परिवार पेंशन का भुगतान उनके जन्म के क्रम से किया जायेगा तथा जो उनमें से छोटा होगा उसे परिवार पेंशन उसके ठीक बड़े व्यक्ति के पात्र नहीं रहने पर ही दी जायेगी ;

- (ii) ऐसे किसी भी पुत्र या पुत्री को जीवन भर के लिए परिवार पेंशन हेतु स्वीकृति देने पूर्व, स्वीकृति प्राधिकारी अपना इस बात से समाधान करेगा कि उसकी विकलांगता इस प्रकार की है कि वह उसे जीविका अर्जित करने से रोकती है। इस साक्ष्य के लिए चिकित्सा अधिकारी से जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी/मेडीकल ज्यूरिस्ट की रैंक से नीचे का नहीं होगा, एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे जिसमें उसकी यथार्थ मानसिक या शारीरिक अक्षमता का यथाशक्त उल्लेख किया जायेगा ; और
- (iii) ऐसे पुत्र या पुत्री के विधिक नैसर्गिक संरक्षक के रूप में परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति या ऐसे पुत्र या पुत्री जो संरक्षक के माध्यम से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, प्रत्येक तीसरे वर्ष में चिकित्सा अधिकारी से, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी/मेडीकल ज्यूरिस्ट की रैंक से नीचे का नहीं होगा, एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा कि वह मानसिक विकार या निःशक्तता से पीड़ित चल रहा है/रही है या शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त या अंधा या बहरा या गूंगा बना हुआ/हुई है।

स्पष्टीकरण :

- (i) कोई पुत्र/पुत्री उसके विवाह की तारीख से या 9500/-रु. प्रतिमास से अधिक की मासिक आय उपार्जित करने पर पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र हो जायेगा/जायेगी। उससे, वैवाहिक स्थिति के बारे में छह माह में प्रमाण- पत्र और मासिक आय के बारे में वार्षिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।
- (ii) ऐसे मामलों में पुत्री के नैसर्गिक/विधिक संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह राजस्थान वित्त निगम में जैसी भी स्थिति हो, प्रत्येक वर्ष एक प्रमाण-पत्र इसका प्रस्तुत करें कि उसका विवाह अभी तक नहीं हुआ है।
- (iii) पात्र कर्मचारी/पेंशनर को परिवार पेंशन का उसके वेतन या पेंशन के अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा यदि पति एवं पत्नी दोनों कर्मचारी हों।

55. आवंटन का क्रम :

- (क) विधवा को, यदि मृतक पुरुष कर्मचारी था, परन्तु यदि उसके एकाधिक उत्तरजीवी पत्नियां हों तो पेंशन उनको बराबर हिस्सों में संदत्त की जायेगी। विधवा की मृत्यु होने पर पेंशन का उसका हिस्सा उसकी पात्र संतान को संदेय होगा। परन्तु यह कि यदि विधवा के बाद कोई संतान जीवित न हो, तो परिवार पेंशन का उसका हिस्सा व्यपगत (Lapse) नहीं होगा अपितु उसका भुगतान अन्य विधवाओं में बराबर के हिस्सा में या यदि अन्य ऐसी विधवा एक ही हो तो उसका उसे पूर्ण रूप में भुगतान किया जायेगा।
- (ख) यदि मृत निगम कर्मचारी या पेंशनर के बाद उसकी विधवा जीवित हो लेकिन उसकी अन्य पत्नी के, जो जीवित नहीं है, पीछे कोई पात्र संतान या संतानें हो तो वह पात्र संतान या संतानें परिवार पेंशन में उस हिस्से के लिए हकदार होगी जिसे माता, निगम कर्मचारी या पेंशनर की मृत्यु के समय यदि जीवित होती तो प्राप्त करती:
- परन्तु यह कि ऐसी संतान या संतानों को या विधवा या विधवाओं को भुगतान योग्य परिवार पेंशन का हिस्सा या हिस्से भुगतान योग्य नहीं रहने पर, वह हिस्सा या हिस्से व्यपगत (Lapse) नहीं होंगे अपितु उनका भुगतान अन्य विधवाओं को एवं/या अन्य संतान या संतानों को अन्यथा

प्रकार से पात्र पाए जाएं, समान हिस्सों में किया जायेगा या यदि केवल एक विधवा या संतान हो तो उस विधवा या संतान को पूर्ण रूप से भुगतान किया जायेगा।

- (ग) जहां मृत निगम कर्मचारी या पेंशनर के बाद उसकी विधवा जीवित हो लेकिन उसकी तलाकशुदा पत्नी या पत्नियों से कोई पात्र संतान या संतानें पीछे जीवित हों तो पात्र संतान या संतानें परिवार पेंशन के ऐसे हिस्से के लिए पात्र होंगे जिसे माता, निगम कर्मचारी या पेंशनर की मृत्यु के समय, यदि उसे तलाक नहीं दिया जाता, तो प्राप्त करती।

परन्तु यह कि ऐसी संतान या संतानों को या विधवा या विधवाओं को भुगतान योग्य परिवार पेंशन का हिस्सा या हिस्से भुगतान योग्य नहीं रहने पर, वह हिस्सा या हिस्से व्यपगत (Lapse) नहीं होंगे अपितु उनका भुगतान उस अन्य विधवा या विधवाओं को एवं/या अन्यथा रूप से पात्र अन्य संतान या संतानों को समान हिस्सों में किया जायेगा या यदि केवल एक विधवा या संतान हो तो उस विधवा या संतान को पूर्ण रूप से भुगतान किया जायेगा।

- (घ) जहां परिवार पेंशन का भुगतान जुड़वां संतानों को किया जाना हो वहां उन संतानों को बराबर के हिस्से में भुगतान किया जायेगा:

परन्तु यह कि जब कोई ऐसी एक संतान पात्र नहीं रहती है तो उसका हिस्सा अन्य संतान को मिलेगा और जब दोनों संतानें पात्र न रहें तो परिवार पेंशन अगली पात्र अकेली संतान/जुड़वां संतानों को मिलेगा।

- (ङ) जहां परिवार पेंशन माता-पिता को संदेय हो, वहां पहले माता के संदत्त की जायेगी और उसकी मृत्यु के पश्चात पिता का संदेय होगी।

56. परिवार पेंशन का एक साथ परिवार के एक से अधिक सदस्यों को भुगतान नहीं किया जायेगा (Family Pension not payable to more than one member of the family at the same time)

- (i) उपरोक्त विनियम में वर्णित यथा-उपबंधित को छोड़कर, परिवार पेंशन का एक साथ परिवार के एक से अधिक सदस्यों को भुगतान करने योग्य नहीं होगी।
- (ii) यदि मृत निगम कर्मचारी/पेंशनर अपने पीछे कोई विधवा /विधुर छोड़ जाता है/जाती है, तो परिवार पेंशन का उस विधवा या विधुर को भुगतान किया जायेगा, उसके न होने पर पात्र संतान को दी जायेगी।
- (iii) संतानों को परिवार पेंशन उनके जन्म के क्रम में मिलेगी तथा उनमें जो छोटा होगा वह परिवार पेंशन के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उससे अधिक आयु की संतान परिवार पेंशन स्वीकृत किये जाने के लिए अपात्र न हो गई हो।

57. परिवार पेंशन सबसे बड़ी संतान को दी जाएगी (Family Pension to be given to the eldest eligible child)

जहां मृत निगम कर्मचारी या पेंशनर अपने पीछे एक से ज्यादा संतानें छोड़ जाता है, वहां सबसे बड़ी संतान विनियमों में के तहत जैसी भी स्थिति हो, में वर्णित अवधि के लिए परिवार पेंशन के लिए हकदार होगी तथा उस अवधि की समाप्ति के बाद अगली संतान परिवार पेंशन की मंजूरी के लिए पात्र होगी।

58. अवयस्क की ओर से संरक्षक को परिवार पेंशन का भुगतान (Payment of family pension to the guardian on behalf of minor)

जहां अवयस्क के लिए इन विनियमों के अधीन पेंशन स्वीकार की जाती है तो उस अवयस्क की ओर से उसका भुगतान संरक्षक को किया जायेगा।

59. पति और पत्नी दोनों निगम/अर्द्ध शासकीय संस्थाओं/सरकार में कर्मचारी होने पर पेंशन का विनियम:

यदि पति और पत्नी दोनों निगम/अर्द्ध शासकीय संस्थाओं/सरकार में कर्मचारी हों और उनमें से किसी एक पर इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों तथा उनमें से एक की सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है, तो मृतक के संबंध में परिवार पेंशन जीवित रहने वाले पति या पत्नी को तथा पत्नी या पति की मृत्यु होने पर, जीवित संतान या संतानों को उन मृत माता-पिता के संबंध में दो परिवार पेंशनें निम्न विनिर्दिष्ट सीमाओं के अध्याधीन रहते हुए, स्वीकार की जाएंगी, अर्थात्

- (i) यदि उत्तरजीवी संतान या संतानें विनियम में वर्णित दर पर दो परिवार पेंशनें आहरित करने के लिए पात्र हैं तो दोनों पेंशनों की राशि 109300/-रु. प्रतिमाह तक सीमित रहेगी।
- (ii) यदि दोनों में से कोई एक परिवार पेंशन विनियम में वर्णित दर पर भुगतान योग्य नहीं रहती है तथा उसके बदले में विनियम 52 और उप-विनियम (i) में वर्णित दर पर पेंशन भुगतान योग्य हो जाती है, तो दोनों पेंशनों की राशि भी 109300/-रु. प्रतिमाह तक सीमित होगी।

60. यदि प्राप्तकर्ता पर निगमकर्मचारी की हत्या करने आदि के अपराध का आरोप लगाया गया है तो परिवार पेंशन निलंबित रखी जायेगी (Suspension of family pension if the recipient is charged with the offence of murdering the Corporation employee, etc) :

(क) यदि किसी ऐसे व्यक्ति पर जो सेवा में रहते हुए निगम कर्मचारी की मृत्यु होने पर इस विनियम के अधीन परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए हकदार है, निगम कर्मचारी की हत्या करने के अपराध का या ऐसे अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरित करने का आरोप लगाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का क्लेम परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए परिवार के अन्य सदस्य या सदस्यों को सम्मिलित करते हुए, उस समय तक निलम्बित रखा जायेगा जब तक कि उसके विरुद्ध प्रारम्भ की गई आपराधिक कार्यवाहियों का निष्कर्ष नहीं निकल जाता है।

(ख) यदि उपरोक्त (क) में वर्णित आपराधिक कार्यवाहियों के समाप्त होने पर, संबंधित व्यक्ति

- (i) निगम कर्मचारी की हत्या के लिए या हत्या हेतु लिए दुष्प्रेरित करने के लिये दोष सिद्ध हो जाता है तो उस व्यक्ति को परिवार पेंशन प्राप्त करने से वंचित किया जायेगा तथा पेंशन का भुगतान निगम कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से परिवार के अन्य पात्र सदस्यों को किया जायेगा,
- (ii) निगम कर्मचारी की हत्या करने के या उस हत्या हेतु दुष्प्रेरित करने के आरोप से दोषमुक्त हो जाता है तो निगम कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से परिवार पेंशन का भुगतान उस व्यक्ति को किया जायेगा।

(ग) उपरोक्त विनियम के खण्ड (क) एवं (ख) के प्रावधान उस परिवार पेंशन पर भी लागू होंगे जो निगम कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर उसकी मृत्यु होने पर भुगतान योग्य होती है।

61. निगम कर्मचारी द्वारा परिवार के ब्यौरों की सूचना (Communication of details of family by the Corporation employee) :

(i) जैसे ही कर्मचारी निगम सेवा में प्रवेश करता है तो वह नियुक्ति प्राधिकारी की विहित प्रपत्र में अपने परिवार का ब्यौरा देगा। यदि कर्मचारी का परिवार न हो तो जैसे ही उसके परिवार होगा वह उसकी सूचना का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार कर्मचारी बाद में उसके परिवार के आकार में परिवर्तन होने पर उसकी सूचना भी वह नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, इस प्रकार दी गई सूचना में उसकी पुत्री के विवाह की सूचना भी सम्मिलित होगी।

(ii) उपरोक्त विनियमों में व्यक्त निःशक्तता किसी संतान में स्वतः दिखाई देती है और वह अपनी जीविका अर्जन में असमर्थ हो जाता है, तो वह इस तथ्य को नियुक्ति प्राधिकारी को डाक्टर के प्रमाण पत्र के साथ जो सिविल सर्जन की रैंक से नीचे का न हो प्रस्तुत करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी उक्त सूचना के प्राप्त होने पर उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा तथा उसे कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में चिपकायेगा। उपरोक्त प्राप्त सूचनाओं की एक रसीद संबंधित कर्मचारी को भी देगा। नियुक्ति प्राधिकारी उपरोक्त समस्त सूचना के प्राप्त होने पर ऐसे परिवर्तन को रिकार्ड पर लेगा।

62. निगम कर्मचारी के परिवार को आनुग्रहिक अनुदान (Ex-gratia grant to the family of the Corporation employee) :

यदि किसी निगम कर्मचारी की इयूटी पर रहते हुए निम्नांकित परिस्थितियों में से किसी एक परिस्थिति में भी मृत्यु हो जाये तो उसे आनुग्रहिक अनुदान अनुज्ञेय होगा, अर्थात्

(क) किसी दुर्घटना में,

(ख) उसके पदीय कर्तव्यों के सम्यक पालन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के कारण,

(ग) उसके पदीय स्थिति के परिणामस्वरूप हुई क्षति के कारण,

(घ) उसकी सेवा से संबंधित कारणों से हुई मानी जा सकने वाली हिंसा द्वारा या

(ङ) विशेष कर्तव्य भार जैसे निर्वाचन इयूटी, जनगणना कार्य और या ऐसे कर्तव्य भार जो राजस्थान वित्त निगम कर्मचारी द्वारा धारित पद के सामान्य कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आते हैं में आनुग्रहिक अनुदान की रकम राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार निगम के बोर्ड (Board of Directors) के निर्णय के अनुसार होगी।

अध्याय- 6

पेंशन/परिवार पेंशन पर महंगाई राहत

(DEARNESS RELIEF ON PENSION/ FAMILY PENSION)

63. पेंशन/परिवार पेंशन पर महंगाई राहत (Dearness relief on pension/ family pension)

मूल्य वृद्धि के प्रति राहत पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को महंगाई राहत के रूप में ऐसी दरों तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए निगम द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार निर्णयाधीन होगी।

अध्याय- 7

पेंशन/अंतःकालीन पेंशन एवं ग्रेच्युटी/ अंतःकालीन रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की मंजूरी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

(PROCEDURE FOR SANCTION OF PENSION/ PROVISIONAL PENSION AND GRATUITY/ PROVISIONAL GRATUITY)

अनुभाग - (I) अंतःकालीन पेंशन
(PROVISIONAL PENSION)

64. प्रोवीजनल पेंशन (PROVISIONAL PENSION) :

- 1) पेंशन प्रकरण स्वीकृति हेतु अग्रेषित करने वाला अधिकारी विनियमों में उल्लेखित कार्यवाही के विभिन्न चरणों का पूर्ण रूप से पालन करेगा कोई ऐसा मामला भी हो सकता है जिसमें विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद भी अग्रेषित करने वाला अधिकारी के लिए संदर्भित पेंशन कागजों को विहित अवधि के भीतर अग्रेषित करना सम्भव नहीं हो या जिसने पेंशन कागजातों को पेंशन स्वीकृति अधिकारी के पास विहित अवधि में अग्रेषित किया जा चुका हो किन्तु जिन्हें पेंशन स्वीकृति अधिकारी ने अग्रेषित करने वाला अधिकारी को पेंशन भुगतान आदेश जारी करने से पूर्व कुछ और सूचना मांगने के लिए लौटा दिया हो, ऐसे मामले में यदि पेंशन अग्रेषित करने वाले अधिकारी को पेंशन भुगतान आदेश जारी करने से पूर्व कुछ और सूचना मांगने के लिए लौटा दिया हो ऐसे मामलों में यदि पेंशन प्रकरण अग्रेषित करने वाले अधिकारी की यह राय हो तो कर्मचारी के इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उसकी पेंशन का अंतिम रूप से निर्धारण एवं निर्णय हो सकने के पूर्व सेवानिवृत्त होने की सम्भावना है तो वह सेवा के अर्हकारी वर्षों का एवं पेंशन के लिए अर्हकारी परिलब्धियों का अत्यन्त सावधानीपूर्वक संक्षिप्त जांच कर निर्धारण करने के लिए कदम उठायेगा। इस प्रयोजन के लिए वह:- (i) उस सूचना पर निर्भर करेगा जो निगम अभिलेखों में उपलब्ध होगी एवं (ii) सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी से सादा कागज पर लिखित वचन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहेगा, जिसमें वह अर्हकारी सेवा की कुल अवधि का, अंतिम रूप से आहरित की गई परिलब्धियों (Emoluments) के ब्यौरों सहित उल्लेख करेगा। लेकिन उसमें सेवा के भंगों (Break in service) एवं सेवा की नॉन क्वालिफाईंग अवधियों को सम्मिलित नहीं करेगा।
- 2) कर्मचारी उपरोक्त वर्णित उप-विनियम (1) के खण्ड (ii) के अनुसार वचन-पत्र प्रस्तुत करते समय उसके नीचे उस वचन-पत्र की सत्यता के संबंध में घोषणा करेगा एवं उस पर हस्ताक्षर करेगा।
- 3) पेंशन प्रकरण अग्रेषित करने वाला अधिकारी उसके बाद अभिलेखों में उपलब्ध सूचना एवं उप-विनियम (i) के अधीन निवृत्त होने वाले कर्मचारी से प्राप्त सूचना के अनुसार सेवा के अर्हकारी वर्षों एवं पेंशन के लिए अर्हकारी परिलब्धियों का निर्धारण करेगा, उसके बाद वह प्रोविजनल पेंशन की राशि का निर्धारण करेगा।
- 4) उपरोक्त वर्णित उप-विनियम 3 के अधीन पेंशन की राशि के अवधारित कर दी जाने के बाद पेंशन प्रकरण अग्रेषित करने वाला अधिकारी निम्न प्रकार आगे कार्यवाही करेगा। वह पेंशन स्वीकृति अधिकारी को संबोधित प्रपत्र में एक स्वीकृति जारी करेगा जिसमें वह उसे निम्नलिखित प्राधिकृत करेगा:-

- (i) प्रोविजनल पेंशन के रूप में उपरोक्त वर्णित उप-विनियम 3 के अधीन यथा अवधारित 100 प्रतिशत पेंशन जो उस समय तक वैद्य रहेगी जब तक कि पेंशन स्वीकृति अधिकारी द्वारा उसे अंतिम रूप से निर्णित न कर दिया जाये।
- (ii) पेंशन प्रकरण अग्रेषित करने वाले अधिकारी से प्रोविजनल पेंशन की स्वीकृति प्राप्त होने पर पेंशन स्वीकृति अधिकारी निश्चित रूप से एक सप्ताह के भीतर प्रोविजनल पेंशन भुगतान आदेश जारी करेगा।
- 5) (i) उपरोक्त वर्णित उप-विनियम 4 के अधीन भुगतान योग्य प्रोविजनल भुगतान की राशि आवश्यक हो, तो अभिलेखों की विस्तृत जांच के पूर्ण किये जाने पर परिवर्तित की जायेगी।
- (ii) परन्तु यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध निगम में प्रचलित ऐसे नियम के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही विचाराधीन हो जिसके लिये लघु शास्ती (Minor Penalty) के दण्ड से दण्डित किये जाने की संभावना हो तो उसे सेवानिवृत्ति पर 100 प्रतिशत प्रोविजनल ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा सकेगा। इसी प्रकार यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध निगम में प्रचलित ऐसे नियम के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही विचाराधीन हो जिसके लिये दीर्घ शास्ती (Major Penalty) के दण्ड से दण्डित किया जा सकता हो ऐसे कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर 50 प्रतिशत प्रोविजनल ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा सकेगा।
- 6) (क) जब अंतिम पेंशन की राशि पेंशन प्रकरण अग्रेषित करने वाले अधिकारी द्वारा अवधारित की गई हो तो पेंशन स्वीकृति अधिकारी (i) पेंशन भुगतान आदेश जारी करेगा। (ii) यदि उपरोक्त वर्णित उप-विनियम 4 के अधीन कर्मचारी को वितरित की गई अंतःकालीन (Provisional) पेंशन की राशि उसके अंतिम रूप से निर्धारण के बाद पेंशन स्वीकृति अधिकारी द्वारा निर्धारित अंतिम पेंशन से अधिक पाई जाये तो पेंशन स्वीकृति अधिकारी भविष्य में देय पेंशन का कम भुगतान कर किशतों में पेंशन की अधिक राशि को वसूल करने के लिए सक्षम होगा।
- 65. निगम में अगले 12 मास के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करना(Preparation of list of Corporation employees due to retire within next 12 months):**
1. महाप्रबन्धक(पीएण्डए) प्रत्येक वर्ष की एक जनवरी को ऐसे समस्त कर्मचारियों की सूची तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा जो निगम के अगले 2 वर्षों के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इस सूची में से प्रत्येक वर्ष में एक जनवरी और एक जुलाई तक एक सूची ऐसे व्यक्तियों की तैयार करेगा जो अगले 6 माह/12 माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
 2. वह सेवानिवृत्ति की तारीख से 12 माह पूर्व संबंधित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तारीख, उनके द्वारा पूरी की जाने वाली सेवानिवृत्ति पूर्व की औपचारिकताओं आदि के बारे में एक पत्र के द्वारा सूचित करेगा।

66. पेंशन के लिए आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण (Submission of application for Pension):

प्रत्येक निगम कर्मचारी उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम 12 माह पूर्व विहित प्रारूप में महाप्रबंधक (पीएण्डए) को औपचारिक पेंशन आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि कर्मचारी 12 माह से अधिक की सेवानिवृत्ति पूर्व की छुट्टियों पर जा रहा हो तो वह पेंशन का आवेदन पत्र छुट्टी पर जाने के समय प्रस्तुत करेगा।

67. पेंशन मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority to sanction Pension):

1. पेंशन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी निम्न प्रकार होंगे -

- | | | | |
|---|------------------|---|--------------------------------|
| 1 | प्रबंध निदेशक | : | समस्त अधिकारियों के संबंध में। |
| 2 | कार्यकारी निदेशक | : | बी एवं सी श्रेणी कर्मचारी। |

दोनों प्राधिकारी विनियम के उपबंधों का पालन करते हुए, विहित प्रारूप में मंजूरी अभिलिखित करेंगे। यदि निगम कर्मचारी द्वारा की गई सेवा अनुमोदित न हो तो उसे इन विनियमों के अधीन अनुज्ञेय पेंशन या उपदान या दोनों की पूरी रकम में ऐसी कमी करनी चाहिए जो इन विनियमों के अधिकथित (Procedure) प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात समुचित समझे।

2. किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन स्वीकृति आदेश जारी करने से पूर्व उसकी सेवाकाल में भुगतान किये गये समस्त वेतनमानों में वेतन निर्धारण संबंधी आदेशों की जांच महाप्रबन्धक(वित्त)/कार्यकारी निदेशक(वित्त) द्वारा प्राधिकृत निगम की लेखा शाखा में कार्यरत उप महाप्रबन्धक(वित्त एवं लेखा) से अन्यून अधिकारी (not lower than DGM(F&A) एवं कार्यकारी निदेशक द्वारा प्राधिकृत कार्मिक और प्रशासन शाखा में कार्यरत उप महाप्रबन्धक (कार्मिक) से अन्यून अधिकारी (not lower than DGM(P&A) के संयुक्त हस्ताक्षरों से ऐसे समस्त वेतन निर्धारण सही होने संबंधी प्रमाण पत्र सेवा पुस्तिकाओं में अंकित किया जावेगा।

68. लिपिकीय गलती का पता लगने के कारण पेंशन का पुनरीक्षण (Revision of Pension due to detection of clerical error) :

- (i) विनियम 16, 17, 18 और 19 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, अंतिम निर्धारण के पश्चात मंजूर की पेंशन में पेंशनर के अलाभकारी रूप में तब तक कमी नहीं की जायेगी, जब तक कि पेंशन की रकम के अवधारण में किसी लिपिकीय गलती या भूल का बाद में पता लगने के कारण पुनरीक्षण आवश्यक न हो। लिपिकीय गलती आदि के कारण पेंशन के पुनरीक्षण के लिए केवल पेंशन मंजूरकर्ता प्राधिकारी द्वारा ही आदेश दिया जायेगा।
- (ii) जब कभी भी उप विनियम (1) के अधीन पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर के लिए अलाभकारी हो, उस पर पेंशन मंजूरकर्ता प्राधिकारी, द्वारा ऐसे पुनरीक्षण के कारण और परिस्थितियां स्पष्ट करते हुए एक नोटिस रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा तामील किया जायेगा और उससे इस प्रकार किये गये अधिक संदाय का प्रतिदाय, नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 3 माह की कालावधि के भीतर, करने की अपेक्षा की जायेगी। नोटिस की पालना करने में उसके विफल रहने पर, पेंशन मंजूर करने वाला सक्षम प्राधिकारी किये गये अधिक संदाय की वसूली भविष्य में एक या अधिक किशतों, जैसा कि वह आदेश विनिर्दिष्ट करे, में पेंशन का कम संदाय करके करने का आदेश देगा।

अनुभाग -(II)

पेंशन के आवेदन पत्र पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया
(PROCEDURE FOR PROCESSING FOR PENSION)

69. पेंशन के कागज पत्र की तैयारी का आरम्भ ; (Commencement of preparation of Pension papers) :

- (i) जो सेवानिवृत्त कर्मचारी इन विनियमों के अंतर्गत पेंशन हेतु विकल्प/पुनर्विकल्प प्रस्तुत करेंगे उनके पेंशन स्वीकृति संबंधी समस्त प्रक्रिया, अपेक्षित राशि जमा कराने पर महाप्रबन्धक(पीएण्डए) द्वारा सम्पादित करायी जावेगी।
- (ii) महाप्रबन्धक (पीएण्डए) कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख के एक वर्ष पूर्व या उसके सेवानिवृत्ति पूर्व की छुट्टी पर जाने की तारीख को जो भी पहले हो, विहित प्रारूप में दो प्रतियों में पेंशन के कागज पत्र तैयार करने का कार्य प्रारम्भ करेगा। पेंशन के कागज पत्रों की तैयारी प्रारम्भ करने के कार्य को इस प्रतीक्षा में विलम्बित नहीं किया जायेगा कि राजस्थान वित्त निगम कर्मचारी उसका पेंशन का औपचारिक आवेदन पत्र वास्तविक रूप से प्रस्तुत कर दे।

70. पेंशन प्रकरण तैयार करना (Preparation of Pension Case) :

सेवा से सेवानिवृत्त होने पर निगम कर्मचारी को उस माह की एक तारीख को पेंशन आहरण कर देना चाहिये जिसमें कि पेंशन देय है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महाप्रबन्धक (पीएण्डए) पेंशन/उपदान की मंजूरी की ओर अग्रसर होने की विभिन्न कार्यवाहियों के लिये निम्नलिखित समय-अनुसूची का अनुसरण करेगा:-

उत्तरदायी अधिकारी का नाम	समय अनुसूची	पूरे किये जाने वाले कार्य
1 महाप्रबंधक (पीएण्डए)	सेवानिवृत्ति की तारीख के 12 माह पूर्व	1 पेंशन कार्य की तैयारी का प्रारम्भ 2 पेंशन केस तैयार करने के प्रयोजनार्थ सेवा पुस्तिका और अभिलेखों की संवीक्षा करना 3 सेवा पुस्तिकाओं को अंतरालों, कमियों आदि का पता लगाकर पूर्ण करना, उनको दूर करने के लिए कदम उठाना। पत्र व्यवहार करना।

पेंशन प्रकरण को सेवानिवृत्ति के आदेश के जारी होने की तारीख से 3 माह की कालावधि के भीतर या उस तारीख से, जिसको किसी निगम कर्मचारी को इन विनियमों के अधीन सेवानिवृत्ति का नोटिस दिया गया है, 3 माह की कालावधि के भीतर निपटाने के प्रयास किये जाने चाहिये।

71. सेवा का सत्यापन (Verification of Service) :

- (i) महाप्रबंधक (पीएण्डए) या प्रबंधक सेवा पुस्तिका का अध्ययन करेगा और स्वयं का इस बात से समाधान करेगा कि उसमें सम्पूर्ण सेवा के सत्यापन का वार्षिक प्रमाण पत्र अभिलिखित किया गया है। सेवा का वास्तविक सत्यापन, शाखा प्रबंधक/ प्रबंधक-कार्मिक द्वारा, यथास्थिति, वेतन-चिट्ठे

निस्तारण पंजी या अन्य सुसंगत अभिलेख के प्रति निर्देश से किया जाना चाहिये और निम्न प्रकार से आवश्यक प्रमाण पत्र अभिलिखित किया जाना चाहिये:

----- से ----- तक की कालावधि की सेवायें मेरे कार्यालय में रखे गये वेतन बिलों/निस्तारण पंजियों या अन्य सुसंगत अभिलेख के प्रति निर्देश से सत्यापित की गई हैं।

हस्ताक्षर

शाखा प्रबंधक/प्रबंधक-कार्मिक

- (ii) यदि कोई सेवा या सेवा का भाग उप विनियम (1) में उल्लेखित रूप में सत्यापित नहीं किया गया है या सत्यापित किये जाने योग्य नहीं है और सेवा की उस कालावधि के बारे में जो मुख्यालय से भिन्न किसी अन्य कार्यालय में या शाखा में की गई है, सेवा के सत्यापन के प्रयोजनार्थ शीघ्रता से उस कार्यालय को लिखा जाना चाहिये जिसमें उसने उस कालावधि के दौरान सेवा की थी। यदि फिर भी सेवा अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण सत्यापित नहीं की जा सके तो कर्मचारी एक सादा कागज पर यह उल्लेख करते हुए लिखित कथन कर सकेगा कि उसने उस कालावधि में वास्तव में सेवा की है और इस कथन के नीचे, कथन की सत्यता के बारे में घोषणा करेगा और ऐसे कथन के समर्थन में ऐसे समस्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा और ऐसी समस्त सूचना देगा जिसे देने की उसकी शक्ति है। पेंशन मंजूर करने में सक्षम प्राधिकारी, लिखित कथन के तथ्यों और उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य और अन्य सूचना पर विचार करने के पश्चात यदि उसका समाधान हो जाये तो, सेवा की उस कालावधि को कर्मचारी की पेंशन की संगणना करने के प्रयोजनार्थ की गई सेवा के रूप में स्वीकार करेगा।
- (iii) सेवा, छुट्टी, निलंबन आदि की समस्त कालावधियों को, जिनको सेवा के रूप में नहीं गिना गया है, विहित प्रारूप में सावधानीपूर्वक अभिलिखित किया जाना चाहिये। यदि आवेदन पत्र विकलांगता पेंशन के लिए हो तो अपेक्षित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सहबद्ध किया जायेगा।

72. अदेयता प्रमाण पत्र (No dues Certificate) :

- (i) सेवानिवृत्त होने वाले प्रत्येक निगम कर्मचारी की यह ड्यूटी होगी कि वह अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व निगम के समस्त देयों को चुका दें।
- (ii) किसी निगम कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख के कम से कम 3 माह पूर्व महाप्रबन्धक(पीएण्डए) अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पत्र लिखेगा –
- (क) प्रबंधक/उप प्रबंधक/सामान्य प्रशासन विभाग/सम्पत्ता आदि केवल ऐसे कर्मचारियों के संबंध में जो निगम के वाहन की अध्यपेक्षा करने या उनको प्रयोग में लेने का हकदार है।
- (ख) महाप्रबन्धक(पीएण्डए): अग्रिमों जैसे भवन, वाहन, खाद्यान अग्रिमों या यात्रा भत्ता/विभागीय अग्रिमों या कर्मचारी के विरुद्ध वेतन/छुट्टी वेतन/यात्रा भत्तों, चिकित्सा या अन्य भत्तों आदि के अधिक संदाय के कारण बकाया कोई अन्य रकम के संबंध में।

- (iii) शाखा/मुख्यालय स्तर पर जिसके अधीन वह सेवानिवृत्ति के समय कार्य कर रहा है उसके विरुद्ध बकाया या उससे वसूली योग्य निगम के कोई भी देयों के संबंध में।

73. सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से मंजूर किया गया पेंशन प्रकरण महाप्रबन्धक (वित्त)/कार्यकारी निदेशक (वित्त) को संदायों के प्राधिकरण के लिए अग्रेषित किया जायेगा।

अध्याय- 8

पेंशन का सरांशीकरण (COMMUTATION OF PENSION)

सामान्य शर्तें (GENERAL CONDITIONS) :

74. (i) पेंशन सरांशीकरण (Commutation of pension) :

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन रूपान्तरण) नियम, 1996 भिन्न-भिन्न हैं और पेंशन परिभाषों की परिभाषा में सिर्फ पेंशन एवं ग्रेच्युटी सम्मिलित होता है। पेंशन सरांशीकरण के संबंध में निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 06.06.2023 में लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य सरकार से निर्देश (वित्त विभाग के आदेश दिनांक 06.07.2023) के अनुसार पेंशन निधि में जमा होने वाली संभावित राशि के अनुसार वित्तीय स्थिति एवं भविष्य की देयताओं को दृष्टिगत रखते हुए ही तथा आंकलन करने के उपरांत पेंशन सरांशीकरण के संबंध में सक्षम स्तर से निर्णय लिया जावेगा।

(ii) पेंशन के सरांशीकरण पर निर्बंधन (Restriction on commutation of pension):

ऐसे निगम कर्मचारी, जिसके विरुद्ध उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां संस्थित हैं या कोई पेंशनर, जिसके विरुद्ध स्टाफ विनियमों के अधीन उक्त कार्यवाहियां उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात संस्थित की गई हैं, ऐसी कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान पेंशन या, यथास्थिति, अंतिम पेंशन के किसी भाग का सरांशीकरण करने का पात्र नहीं होगा।

75. पेंशन के सरांशीकरण की सीमा (Limit of commutation of pension) :

निगम कर्मचारी उसकी पेंशन के एक तिहाई से अनधिक भाग के एकमुश्त संदाय के लिए सरांशीकरण का हकदार होगा। आवेदक, पेंशन के उस भाग को, जिसका वह सरांशीकरण चाहता है, सरांशीकरण के आवेदन पत्र के प्रारूप में उपदर्शित करेगा और या तो पेंशन के एक तिहाई की अधिकतम सीमा या न्यूनतम सीमा, जो वह सरांशीकरण कराना चाहे, उपदर्शित कर सकेगा। सरांशीकरण के प्रयोजनार्थ रुपये की भिन्न को छोड़ दिया जायेगा।

76. पेंशन के सरांशीकरण का अत्यांतिक होना (Commutation of pension to become absolute)

पेंशन के सरांशीकरण, ऐसे आवेदक के मामले में, जो उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के एक वर्ष के भीतर-भीतर सरांशीकरण के लिए आवेदन करता है, उस तारीख को आत्यांतिक होगा जिसको आवेदन पत्र निगम के मुख्यालय में प्राप्त होता है और अन्य मामलों में उस तारीख को होगा जिसको चिकित्सा प्राधिकारी प्रारूप सीपी-(IV) के भाग (I) में स्वास्थ्य रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है, परन्तु:-

- (क) किसी ऐसे निगम कर्मचारी के मामले में, जो उसकी पेंशन मुख्यालय से आहरित कर रहा हो, सरांशीकरण के कारण पेंशन की रकम में कमी, चेक/ड्राफ्ट/आरटीजीएस द्वारा पेंशन के सरांशीकृत मूल्य की प्राप्ति की तारीख से प्रवर्तित होगी, या
- (ख) किसी ऐसे निगम कर्मचारी के मामले में, जो निगम के बैंकों की शाखा से या पेंशन के संदाय के प्रयोजनार्थ निगम द्वारा नाम निर्देशित किसी अन्य शाखा से पेंशन आहरित कर रहा है, सरांशीकरण के कारण पेंशन की रकम में कमी, उस तारीख से प्रवर्तित होगी जिसको सरांशीकृत मूल्य बैंक द्वारा आवेदक के उस खाते में जमा किया जाये जिसमें पेंशन जमा की जाती है।
- (ग) उस तारीख की, जिसको पेंशन का सरांशीकृत मूल्य आवेदक के बैंक खाते में जमा किया गया था, उस संवितरक प्राधिकारी द्वारा, जिसने पेंशन का सरांशीकृत मूल्य प्राधिकृत किया है, पेंशन संदाय आदेश के दोनों अर्द्ध भागों पर प्रविष्टि की जायेगी।

77. पेंशन के सरांशीकृत मूल्य को प्राप्त करने के पूर्व किसी आवेदक की मृत्यु (Death of an applicant before receiving the commuted value of pension) :

यदि कोई निगम कर्मचारी सरांशीकृत मूल्य को प्राप्त करने के पूर्व जिस तारीख को वह आत्यांतिक हो या उसके पश्चात सरांशीकृत मूल्य प्राप्त किये बिना मर जाता है तो सरांशीकृत मूल्य उसके वारिसों को दिया जायेगा।

78. पेंशन के सरांशीकृत मूल्य की संगणना (Calculation of commuted value of pension) :

किसी निगम कर्मचारी को एक मुश्त संदेय रकम ऐसी मूल्य सारणी के अनुसार संगणित की जायेगी जो समय-समय पर विहित की जाये और उस तारीख को जिसको सरांशीकरण आंत्यांतिक हो आवेदक पर लागू होती है।

79. अंतिम पेंशन का भूतलक्षी पुनरीक्षण ; (Retrospective Revision of final pension) :

ऐसे किसी निगम कर्मचारी को जिसने उसके पेंशन के भाग को सरांशीकृत करवाया हो और सरांशीकरण के बाद उसकी पेंशन निगम के विनिश्चय के परिणामस्वरूप पुनरक्षित हो गई हो जिसको मूल पेंशन मंजूर की गई थी, भूतलक्षी रूप से बढ़ गई हो तो कर्मचारी को बढ़ी हुई पेंशन के प्रति निर्देश से अवधारित सरांशीकृत मूल्य और पहले ही प्राधिकृत सरांशीकृत मूल्य के बीच के अंतर का संदाय किया जायेगा। अंतर के संदाय के लिए कर्मचारी के नये सिरे से आवेदन करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी किन्तु उसको अपने आशय की सूचना देनी होगी।

80. स्वास्थ्य परीक्षण के बिना पेंशन के सरांशीकरण की प्रक्रिया (Procedure for commutation of pension without medical examination) :

पात्रता: ऐसा कोई निगम कर्मचारी जिसको अधिवार्षिकी या सेवानिवृत्ति या प्रतिकारात्मक पेंशन मंजूर की गई है, उसकी स्वास्थ्य परीक्षण के बिना पेंशन के एक भाग को कम्यूटेशन करवाने का पात्र होगा। बशर्ते की वह सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष समाप्त होने के पूर्व विहित प्रारूप में पेंशन के कम्यूटेशन के लिए आवेदन करे और मुख्यालय से अनुमति प्राप्त करे।

81. आवेदन पत्र (Application) :

1. पेंशन के कम्यूटेशन का आवेदन सेवानिवृत्ति के पश्चात एक वर्ष के भीतर विहित प्रारूप में निगम मुख्यालय पर महाप्रबंधक (पीएण्डए) को किया जायेगा, यदि वह स्वास्थ्य परीक्षण के बिना कम्यूटेशन चाहता है।
2. एक वर्ष की कालावधि उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से गिनी जायेगी, चाहे सेवानिवृत्ति आदेश किसी भूतलक्षित (Retrospective) तारीख से जारी किया गया हो और ऐसे मामलों में जहां विभागीय या न्यायायिक कार्यवाहियां संस्तुत की गई हों तो विभागीय या न्यायायिक कार्यवाहियों के परिणामिक आदेशों के जारी होने की तारीख से गिनी जायेगी।
3. यदि ऊपर विनियम-1 के विहित प्रारूप में आवेदन आवेदक की सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के बाद मुख्यालय में प्राप्त होता है तो मुख्यालय कर्मचारी को सूचित करेगा कि:-
 - (क) वह स्वास्थ्य परीक्षण के बिना पेंशन के भाग के कम्यूटेशन का पात्र नहीं होगा।
 - (ख) यदि वह पेंशन के भाग को कम्यूटेट कराना चाहता है तो नये सिरे से विहित प्रारूप में आवेदन करेगा, जिससे कि आगे वर्णित विनियम में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

82. कम्यूटेशन मूल्य का प्राधिकरण (Authorisation of commutation value)

1. महाप्रबंधक (पीएण्डए) विहित प्रारूप के प्राप्त होने पर सत्यापित करेगा कि विहित प्रारूप में कर्मचारी द्वारा दी गई सूचना सही है और यह कि वह स्वास्थ्य परीक्षण के बिना उसकी पेंशन के एक भाग का कम्यूटेशन प्राप्त करने का हकदार है और उसके बाद विहित कम्यूटेशन सारणी के अनुसार पेंशन का कम्यूटेट मूल्य अवधारित करने के बाद प्रकरण को महाप्रबंधक (वित्त)/कार्यकारी निदेशक (वित्त) को समीक्षा करने के लिए और संवितरक प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत पत्र जारी करने के लिए कर्मचारी को सूचना देते हुए अग्रेषित करेगा।
2. संवितरक प्राधिकारी पेंशन के कम्यूटेशन मूल्य के संदाय का आदेश प्राप्त होने पर उस तारीख की प्रविष्टि करेगा, जिससे पेंशन के भाग के कम्यूटेशन की वजह से पेंशन की रकम में कमी की जानी है।

83. स्वास्थ्य परीक्षण के बाद पेंशन के कम्यूटेशन की प्रक्रिया (Procedure for commutation of pension after medical examination) :

पात्रता: निम्नलिखित मामलों में किसी निगम कर्मचारी को केवल स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही पेंशन का कम्यूटेशन अनुज्ञात किया जायेगा:-

1. ऐसा कर्मचारी जिसको सेवा में शास्ति के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया हो और इन विनियमों के अधीन पेंशन मंजूर की गई हो।
2. ऐसा कर्मचारी जिसने विनियमों में विनिर्दिष्ट पेंशनों में से किसी एक पर सेवानिवृत्त होने पर सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर कम्यूटेशन के लिए आवेदन नहीं किया हो।

84. पेंशन के कम्यूटेशन के लिए आवेदन पत्र (Application for commutation of Pension) :

1. निगम कर्मचारी विहित प्रारूप में मुख्यालय पर महाप्रबन्धक(पीएण्डए) को आवेदन करेगा जो प्रारूप के कार्यालय द्वारा पूर्ण करने वाले भाग को पूर्ण करने के बाद ऐसे सरकारी चिकित्सालय के अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए विहित प्रारूप में अनुरोध करेगा, जहां कर्मचारी स्वास्थ्य परीक्षण करवाना चाहता है और उसको निम्नलिखित दस्तावेज अग्रेषित करेगा:-
 - (i) पूर्ण किया गया विहित प्रारूप, मूल रूप में
 - (ii) कर्मचारी की 2 फोटो जिनमें से एक अटैच होगी
 - (iii) विहित प्रारूप की प्रति, अतिरिक्त प्रति सहित
 - (iv) इस बारे में कर्मचारी की रिपोर्ट या विवरण कि क्या उसने पूर्व में उसकी पेंशन के भाग को कम्यूटेड करवाया या उसके कम्यूटेशन के प्रार्थना पत्र को पूर्व में अस्वीकार कर दिया गया।
2. सरकारी चिकित्सा के अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को संबोधित पत्र की एक प्रति निगम कर्मचारी को पृष्ठांकित की जायेगी।
3. सरकारी चिकित्सालय का अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी उप विनियम (1) में निर्दिष्ट दस्तावेज प्राप्त होने पर:-
 - (क) कर्मचारी द्वारा विहित प्रारूप में उपदर्शित स्थान के निकटस्थ उपलब्ध स्थान पर चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण करवाने की व्यवस्था करेगा।
 - (ख) निर्दिष्ट दस्तावेज विनियम में यथा उपबंधित रीति में कर्मचारी का परीक्षण करने का निर्देश सहित भेजेगा।
 - (ग) कर्मचारी को यह सूचित करेगा कि उसे कहां और कब स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उपस्थित होना है या यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा प्राधिकारी को ऐसे परीक्षण की तारीख और समय की सूचना कर्मचारी को देने के लिए आवश्यक निर्देश देगा।
 - (घ) स्वास्थ्य परीक्षण की तारीख निश्चित करने में यह निश्चित किया जायेगा कि स्वास्थ्य परीक्षण कर्मचारी की अगली जन्म तारीख से पूर्व हो जाये।
 - (ङ) यदि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी की वास्तविक आयु में वर्षों की वृत्ति के आधार पर कम्यूटेशन स्वीकार करने से इंकार कर दिया जाये तो कम्यूटेशन चाहने वाला कर्मचारी द्वितीय स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आवेदन करेगा, इस दशा में चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
 - (च) कर्मचारी से स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ऐसी फीस का संदाय करने की अपेक्षा की जायेगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये।

85. स्वास्थ्य परीक्षण की प्रक्रिया (Procedure for Medical examination) :

स्वास्थ्य परीक्षण की प्रक्रिया चिकित्सा प्राधिकारी/बोर्ड द्वारा जैसी भी स्थिति हो निर्धारित की जायेगी।

86. सारणी में विनिर्दिष्ट मूल्य का उपांतरण (Modification in the value specified in the table)

1. यदि सारणी में विनिर्दिष्ट मूल्य विनियम के निर्बंधों के कम्यूटेशन के अत्यांतिक (out of date) होने के पूर्व किसी भी समय कम्यूटेशन कर दिया जाये तो संदाय इस प्रकार कम्यूटेड मूल्य के अनुसार किया जायेगा।
2. जहां इस प्रकार कम्यूटेड सारणी के प्रति निर्देश से संगणित सरांशीकृत मूल्य कम्यूटेशन से पूर्व प्रवर्तित सारणी के प्रति निर्देश से अवधारित मूल्य की अपेक्षा कम अनुकूल हो वहां महाप्रबन्धक(पीएण्डए) कर्मचारी को पुनःरक्षित मूल्य के बारे में सूचित करेगा। उसे यह सूचना देगा कि वह ऐसी सूचना की प्राप्ति की 14 दिन के भीतर-भीतर महाप्रबन्धक (पीएण्डए) को लिखित में नोटिस देकर आवेदन को वापस लेने के लिए स्वतंत्र है।

87. महाप्रबन्धक(वित्त)/कार्यकारी निदेशक (वित्त) द्वारा सरांशीकृत मूल्य के संदाय का प्राधिकरण
 {(Authorisation of payment of commuted value by the General Manager (Finance)/Executive Director (Finance))}:

उपरोक्त विनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए महाप्रबन्धक(पीएण्डए) चिकित्सा प्राधिकारी से विनियम में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के प्राप्त होने पर उनको संबंधित संवितरक प्राधिकारी को आदेश जारी करने के लिए महाप्रबन्धक(वित्त)/कार्यकारी निदेशक(वित्त) को अविलम्ब अग्रेषित करेगा और निम्नलिखित विशिष्टियां भेजेगा –

1. कम्यूटेड पेंशन की रकम, पेंशन कम्यूटेशन के मूल्य की रकम और वह तारीख जिससे कम्यूटेशन आत्यांतिक हुआ हो।
 2. अवशिष्ट पेंशन की रकम
 3. कर्मचारी के फोटो की चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित प्रति
 4. वह तारीख जिससे मूल पेंशन की रकम में कमी की जानी चाहिए
- 88. (1)** कोई निगम कर्मचारी जो निगम की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है और जिसने समय-समय पर यथा संशोधित इन विनियमों के अधीन उसकी मूल पेंशन के एक तिहाई के अध्यधीन रहते हुए उसकी पेंशन के एक भाग को सरांशीकृत कराया है, सरांशीकरण की तारीख से 14 वर्ष की कालावधि समाप्त होने के बाद या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, जो भी पश्चातवर्ती हो उसके कम्यूटेड पेंशन भाग के प्रत्यावर्तन के लिए अनुरोध का फायदा उस माह जिससे वह कम्यूटेशन की तारीख से 14 वर्ष पूरे करता है या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, जो भी पश्चातवर्ती हो, के आगामी माह की तारीख से अनुज्ञात किया जायेगा, तब उसे वह पूरी पेंशन अनुज्ञात की जायेगी जो वह तब आहरित करता यदि पेंशन के भाग को कम्यूटेशन नहीं किया जाता।
- (2) पेंशन के प्रत्यावर्तित भाग को पुनः कम्यूटेड करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।
 - (3) ऐसा कोई कर्मचारी जो पेंशन के कम्यूटेड भाग के प्रत्यावर्तन का पात्र है, महाप्रबन्धक(पीएण्डए) को विहित प्रारूप में आवेदन करेगा।
 - (4) महाप्रबन्धक (पीएण्डए) पेंशनर को सूचना देते हुए पूर्ण पेंशन के प्राधिकरण के लिए प्रकरण को महाप्रबन्धक(वित्त)/कार्यकारी निदेशक (वित्त) को अग्रेषित करेगा और पुराने पेंशन संदाय आदेश के आरपार लाल स्याही से रेखा खेंचकर उसके हस्ताक्षर करके उसे रद्द करते हुए नया आदेश जारी करेगा।

अध्याय - 9

पेंशन का संदाय (PAYMENT OF PENSION)

89. संदाय की तारीख (Date of payment) :

इन विनियमों के अधीन संदेय पेंशन उस तारीख से प्रभावी होती है जिसको पेंशनर निगम सेवा में न रहे।

90. उपदान का संदाय (Gratuity payment) :

निगम के महाप्रबन्धक (वित्त)/कार्यकारी निदेशक (वित्त) का प्राधिकार प्राप्त होने पर उपदान एकमुश्त संदत्त किया जाता है न कि किश्तों में।

91. पेंशन के संदाय की प्रक्रिया (Procedure for payment of Pension) :

- (i) पेंशन उस माह के, जिससे यह संबंधित हो, अगले मास के प्रथम दिन को या उसके पश्चात संदेय होगी।
- (ii) प्रत्येक पेंशनर को एक पेंशन संदाय आदेश जारी किया जायेगा जिसके आधार पर उसको मासिक पेंशन संदत्त की जायेगी।
- (iii) महाप्रबन्धक (वित्त)/कार्यकारी निदेशक(वित्त) पेंशन संदाय आदेश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा। पेंशन संदाय आदेश 2 प्रतियों में जारी किया जायेगा, जिसकी एक प्रति संवितरक प्राधिकारी की होगी जिसे संवितरक का भाग कहा जाता है और दूसरी प्रति पेंशनर को देने के लिए होगी जिसे पेंशनर का भाग कहा जाता है। संवितरक प्राधिकारी, पेंशन संदाय आदेश प्राप्त होने पर, पेंशनर का भाग पेंशनर को देगा जब वह उसको पेंशन का प्रथम संदाय प्राप्त करने के लिये बुलाये।
- (iv) किये गये प्रत्येक संदाय को पेंशन संदाय आदेश के संवितरक भाग और पेंशनर के भाग, दोनों के पीछे दर्ज किया जायेगा।
- (v) प्रथम बार एक वर्ष से अधिक की बकाया पेंशन का संदाय किसी भी परिस्थिति में महाप्रबन्धक(वित्त)/कार्यकारी निदेशक(वित्त) के विशेष आदेशों के बिना नहीं किया जाना चाहिये।
- (vi) पेंशनर, पेंशन संदाय आदेश से उस समय, जब वह संवितरक अधिकारी के कार्यालय से पेंशन आहरित करे, मिलान करके पहचान कर लेने के पश्चात व्यक्तिगत रूप से संदाय ले सकता है:-
 - (क) यदि कोई पेंशनर शारीरिक रुग्णता (bodily illness or infirmity) या निरोग्यता के परिणामस्वरूप या कोई महिला पेंशनर सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने की अभ्यस्थ नहीं होने से या किसी अन्य कारण से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वह निगम के किसी प्राधिकारी द्वारा जो सहायक प्रबंधक की रैंक से नीचे का न हो या किसी मजिस्ट्रेट, पोस्टमास्टर या बैंक अधिकारी, या राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी या ऐसे विख्यात और विश्वसनीय किसी व्यक्ति द्वारा जो संवितरक अधिकारी का परिचित हो द्वारा हस्ताक्षरित जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके पेंशन प्राप्त कर सकता है/सकती है।
 - (ख) पेंशन किसी एजेंट या प्रतिनिधी के माध्यम से भी आहरित की जा सकती है किन्तु उसके पास पेंशनर की ओर से संदाय प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा नाम निर्देशित एजेंट या प्रतिनिधी

को पेंशन का संदाय करने हेतु पेंशनर का लिखित प्राधिकार अवश्य होना चाहिये। ऐसे मामलों में पृष्ठांकन संदाय प्राप्त किया पर स्वयं पेंशनर द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और एजेंट या प्रतिनिधी द्वारा संदाय वास्तव में प्राप्त करने के प्रतीक स्वरूप एक प्रथम रसीद पृष्ठांकित की जायेगी जिस पर टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में प्रत्येक संदाय के समर्थन में जीवित होने का प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा, जो कि इस उपरोक्त उप-विनियम के खण्ड-(क) में उल्लेखित है।

- (vii) उपरोक्त उप-विनियम (vi) में निर्दिष्ट समस्त मामलों में, संवितरक प्राधिकारी को, धोखे के निवारण हेतु पूर्ण सावधानी (Precautions) अवश्य रखनी चाहिए और एक वर्ष में कम से कम एक बार, पेंशनर की निरंतर विद्यमानता के बारे में किसी अन्य सबूत की उसके अतिरिक्त, जो कि जीवित होने के प्रमाण पत्र के रूप में दिया गया है अपेक्षा अवश्य करनी चाहिये। इस प्रयोजनार्थ पेंशनर से यह अपेक्षा की जाये कि जब कभी भी संवितरक अधिकारी द्वारा चाहा जाये, वह सत्यापन के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो, किन्तु प्रत्येक छह माह में एक बार से अधिक नहीं।
- (vii) कोई ऐसा पेंशनर, जो भारत का निवासी नहीं है, उसके पेंशन उस देश में भारत के बैंक या राजनयिक प्रतिनिधी को, प्रत्येक अवसर पर जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके बैंक के माध्यम से आहरित कर सकेगा।

92. पेंशन का संवितरण(Disbursement of Pension) :

- (i) पेंशनर को पेंशन का संदाय करने के लिए मुख्यालय में उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) संवितरक अधिकारी होगा।
- (ii) पेंशन मुख्यालय द्वारा पेंशनर को नियत तारीख पर संदत्त की जायेगी।

93. पेंशन संदाय आदेश का नवीनीकरण या खो जाने पर नया जारी किया जाना(Renewal of issue of New Pension, Payment order on lost) :

- (i) जब पेंशन संदाय आदेश का पिछला भाग भर जाये या जब पेंशनर का भाग विकृत हो जाये या कटफट जाये तो संवितरक अधिकारी द्वारा इन दोनों भागों का नवीनीकरण किया जायेगा।
- (ii) यदि किसी पेंशनर के पेंशन संदाय आदेश का उसका भाग खो गया हो तो संवितरक अधिकारी द्वारा नया पेंशन संदाय आदेश जारी किया जायेगा और मुख्यालय पर रखे गये रजिस्टर/खाताबही/खाते में इस आशय का आवश्यक टिप्पण किया जायेगा।

94. व्यपगत या समपहरण होना(Lapses or Forfeiture) :

- (i) यदि कोई पेंशन एक वर्ष से अधिक समय तक अनाहरित रहती है तो वह संदेय नहीं रह जाती। यदि कोई पेंशनर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है तो संवितरक अधिकारी संदाय का नवीनीकरण कर सकेगा किन्तु पेंशन की बकाया का संदाय नहीं किया जाना चाहिये यदि उसका संदाय पहली बार किया जा रहा हो या यदि बकाया की रकम 7200/-रु. से अधिक हो, जब तक कि प्रबंधक(वित्त) द्वारा महाप्रबंधक (वित्त)/कार्यकारी निदेशक (वित्त) से मंजूरी प्राप्त न कर ली जाये।

- (ii) (क) पेंशनर की मृत्यु होने पर, वास्तव में देय बकायाओं का संदाय वारिसों को किया जा सकेगा बशर्ते कि वे मृत्यु के एक वर्ष के भीतर आवेदन कर दें। इसके पश्चात उनका संदाय महाप्रबन्धक (वित्त)/कार्यकारी निदेशक (वित्त) की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता। तथापि यदि बकाया 2000/-रु. से अधिक न हो तो उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) उसके स्वयं के प्राधिकार से बकाया का संदेय कर सकेगा।

(ख) उपरोक्त वर्णित उप-विनियम के खण्ड (क) के उपबंधों के अधीन रहते हुये मृतक पेंशनर की बकायाओं का संदाय उसके वारिसों को विधिक प्राधिकार प्रस्तुत किये बिना ही महाप्रबन्धक (वित्त)/कार्यकारी निदेशक(वित्त) के आदेशों के अधीन, दावा करने वालों के अधिकारों और स्वत्व की ऐसी जांच करने के पश्चात जो पर्याप्त समझी जाये, क्षतिपूर्ति बंधी पत्र ऐसी प्रतिभूतियों सहित, जो अपेक्षित हों, प्रस्तुत करने पर किया जा सकेगा। शंका या विवाद की दशा में संदाय केवल विधिक प्राधिकार प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को ही किया जाना चाहिए।

बशर्ते कि वे मृत्यु के एक वर्ष के भीतर आवेदन कर दें। इसके पश्चात उनका संदाय महाप्रबन्धक (वित्त)/कार्यकारी निदेशक (वित्त) की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता। तथापि यदि बकाया 2000/-रु. से अधिक न हो तो उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) उसके स्वयं के प्राधिकार से बकाया का संदेय कर सकेगा।

95. पेंशन आदि के आवेदन पत्र, परीक्षा, मंजूरी और प्राधिकरण के प्रारूप वैसे ही होंगे जैसे कि निगम द्वारा निर्धारित किये जावेंगे।
96. इन विनियमों में उल्लेखित विभिन्न प्रावधानों के अनुसार अधिकतम देय राशि का भुगतान किया जा सकेगा परन्तु इस प्रकार देय राशि राज्य सरकार में प्रचलित संबंधित नियमों के अनुसार प्रावधित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होगी।
97. उपरोक्त "राजस्थान वित्त निगम कर्मचारी पेंशन विनियम-2023" में जहाँ जहाँ राज्य सरकार के नियमों से अन्तर या व्याख्या का प्रश्न है तो राज्य सरकार के नियमों में उल्लेखित प्रावधान लागू रहेंगे। यदि वित्त निगम द्वारा संदर्भित नियमों से भिन्न विनियमों के अन्तर्गत कोई प्रावधान किया जाता है तो इस संदर्भ से राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION

OPTION FORM

(3 copies – one copy should be pasted on service book, one copy may be returned to employee after accepting option and one copy to be retained in official record.)

Name of the Organization: **RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION**

A. To be filled by employees (in service/retired) and also eligible family member of deceased employee who were earlier governed by CPF/GPF for switching over to GPF linked Pension Scheme as governed by the RFC Employees' Pension Regulations, 2023.

1. I, _____ (Name) _____ (Designation) the undersigned, hereby opt / re-opt the GPF linked Pension Scheme as governed by the RFC Employees' Pension Regulations, 2023 and other related regulations as amended from time to time.

2. I hereby declare that :

(a) I have not filed any court case in any court of law against RFC and/or State of Rajasthan relating to pension and other retiral/pensionary benefits.

(b) I have withdrawn the court case filed by me or through Employees/Officers Association against RFC and/or State of Rajasthan before _____ (name of Court bearing case no. & title) _____ and as on date no court case is pending filed by me or through Association regarding pension and other retiral/pensionary benefits.

3. I am aware that the option for pension once exercised will be final and irrevocable.

1. Full Name : _____
2. Designation : _____
3. Department/Office : **RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION**
4. CPF No. : _____
5. Employee ID/GPF SAB No. : _____

Note: If dependent of the family member is applying for Pension Scheme then relevant documents should be attached to ascertain eligibility under pension related provisions.

Signature of employee/retired employee/
Dependent member with date

Witnesses:

Witness 1. Signature and date
Name in full :
Designation:

Witness 2. Signature and date
Name in full :
Designation:

B. To be filled by office:

Received from Mr./Ms. _____ (Name & designation)
regarding option for GPF linked Pension Scheme as governed by the RFC
Employees' Pension Regulations, 2023.

Note: In case of family pension the relevant documents should also be submitted with option form.

(Signature & Seal, Name and
designation of receiving officer)

Date:

**C. To be filled by the authorized officer of the Rajasthan Financial Corporation
who is accepting the option**

(i) Details of amount deposited/transferred one time by the employee/dependent with
interest (as applicable) Rs. _____

(ii) Details of amount deposited/transferred one time by the employer (as applicable)
Rs. _____

(iii) Total amount one time deposited/transferred Rs. _____

Note:

1. This option form shall be accepted only after deposition/transfer of one time amount as per order issued by Rajasthan Financial Corporation.
2. The last date of deposition/transfer of all amount is 31.07.2023. However, in case there is difference in calculated amount and the deposited/transferred amount, the remaining amount can be deposited/transferred by the employee/employer/dependent one time upto 16.08.2023.
3. It is certified that the calculation of deposited/transferred amount has been checked & the amount has been deposited/transferred in the RFC Pension Fund on _____

As all due amount has been deposited/transferred in the pension fund, therefore the option of Mr./Ms. _____ is accepted for pension/family pension from _____ (date).

Dated:

Time:

Signature with Seal
of the designation officer of
Rajasthan Financial Corporation

राजस्थान वित्त निगम
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 26, 2023

संख्या आरएफसी/एफ.पीए 23 (16)/470 :- दी स्टेट फाईनेन्सियल कारपोरेशन्स एक्ट, 1951 की धारा 48 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान वित्त निगम के संचालक मण्डल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से विचार विमर्श के पश्चात तथा राज्य सरकार की पूर्वानुमति लेकर राजस्थान वित्त निगम कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि विनियम, 2023 की संरचना की है, जिसका विस्तृत पाठ्य निम्नानुसार होगा :-

राजस्थान वित्त निगम कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि
विनियम/अभिदान
(RFC GPF REGULATIONS)

1.	<p>शीर्षक एवं लागू होने की तिथि -</p> <p>(i) ये विनियम राजस्थान वित्त निगम सामान्य प्रावधायी निधि विनियम 2023 कहलायेंगे।</p> <p>(ii) ये विनियम इस अधिसूचना के जारी होने के उपरान्त प्रभावी होंगे।</p> <p>(iii) ये नियम जीपीएफ लिंकड पेंशन स्कीम अंगीकृत करने वाले सेवारत कर्मचारियों पर ही लागू होगा।</p>
2.	<p>परिभाषाएँ:- इन विनियमों में, जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो:-</p> <p>(i) "खाता" से अभिप्राय विभाग के पास खाताधारक के उस खाते से है जिसमें विभाग द्वारा उसकी समस्त जमा राशि एवं ब्याज जमा किया जाता है एवं आहरण नाम लिखा जाता है।</p> <p>(ii) "खाताधारक" से अभिप्राय उस अभिदाता से है जिसका इन नियमों के अन्तर्गत खाता संधारित किया जायेगा।</p> <p>(iii) "अभिदाता" से अभिप्राय उस राजस्थान वित्त निगम कार्मिक से है जिसका अभिदान इन नियमों के अंतर्गत प्राप्त होगा।</p> <p>(iv) "विभाग" से तात्पर्य राजस्थान सरकार के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से है।</p> <p>(v) "निदेशक" से अभिप्राय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निदेशक से है एवं इसमें विभाग में नियुक्त वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/संयुक्त/उप एवं सहायक निदेशक सम्मिलित हैं।</p> <p>(vi) "सरकार" से अभिप्राय राजस्थान सरकार से है।</p> <p>(vii) "कार्यालयाध्यक्ष" से अभिप्राय राजस्थान वित्त निगम के प्रबन्ध निदेशक से है।</p> <p>(viii) "राज्य" से अभिप्राय राजस्थान राज्य से है।</p> <p>(ix) "निधि" से अभिप्राय सामान्य प्रावधायी निधि से है जिसमें विभाग द्वारा सामान्य प्रावधायी निधि योजना से संबंधित समस्त प्राप्ति एवं भुगतान सम्मिलित है।</p>

	<p>(x) "वित्तीय वर्ष" से अभिप्राय 1 अप्रेल से प्रारम्भ होने वाला एवं 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष से है।</p> <p>(xi) "परिवार" से अभिप्राय-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "पुरुष अभिदाता" के मामले में पत्नी अथवा पत्नियां, माता-पिता, बच्चे, अवयस्क भाई, अविवाहित बहिन, मृत पुत्र की विधवा एवं बच्चे और अगर अभिदाता के माता पिता जीवित नहीं हैं तो दादा-दादी। परन्तु अगर अभिदाता यह सिद्ध कर दे कि उसकी पत्नी न्यायिक रूप से उससे पृथक् कर दी गई है या जिस समुदाय से वह संबंधित है, उस की रूढ़ीजन्य विधि के अधीन वह भरण पोषण की हकदार नहीं रही है तो वह विनियमनों के अन्तर्गत परिवार की सदस्य तब तक नहीं मानी जायेगी जब तक कि अभिदाता बाद में राजस्थान वित्त निगम के माध्यम से निदेशक को इस संबंध में सदस्य माने जाने के लिए लिखित में सूचित नहीं कर देता है। 2. "महिला अभिदाता" के मामले में पति, माता पिता, बच्चे, अवयस्क भाई, अविवाहित बहिन, मृत पुत्र की विधवा एवं बच्चे और जहां पर माता पिता जीवित नहीं हैं तो दादा दादी। परन्तु यदि अभिदाता द्वारा राजस्थान वित्त निगम के माध्यम से निदेशक को लिखित में अपने पति को परिवार से अपवर्जित करने की इच्छा अभिव्यक्त की जाती है तो पति इन नियमों के संदर्भ में अभिदाता के परिवार का सदस्य तब तक नहीं माना जायेगा जब तक कि अभिदाता बाद में ऐसी सूचना को लिखित में निरस्त नहीं कर दें। <p>(xii) "वेतन" से अभिप्राय-कर्मचारी द्वारा प्राप्त किये जाने वाले निम्नांकित मासिक वेतन से है –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. वेतन, विशेष वेतन या उसकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर स्वीकृत वेतन के अतिरिक्त जो उसके द्वारा स्थाई (Substantively) या स्थानापन्न (Officiating) से धारण किये गये पद के लिये स्वीकृत किय गया है या जिसे वह अपनी पदीय स्थिति के कारण प्राप्त करने का पात्र है एवं 2. विशेष वेतन एवं व्यक्तिगत वेतन, एवं 3. अन्य राशि जो बोर्ड द्वारा विशेष रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत की गई हो। <p>(xiii) "ई-पासबुक/पासबुक" से आशय उस पासबुक से है जो पासबुक के रूप में एसआईपीएफ पोर्टल पर प्रदर्शित होती है। इसमें पूर्व संधारित "पासबुक" भी सम्मिलित है जो अभिदाता को इन विनियमनों के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम द्वारा जारी की गई है एवं सत्यापित की गई है और जो स्कैन प्रति (Scanned Copy) के रूप में एसआईपीएफ पोर्टल पर प्रदर्शित होती है।</p> <p>(xiv) "सामान्य प्रावधायी निधि योजना" से अभिप्राय इन विनियमों में वर्णित सामान्य प्रावधायी निधि योजना से है जिनमें सामान्य प्रावधायी निधि सैब (जीपीएफ-सैब) भी सम्मिलित है।</p> <p>(xv) "सामान्य प्रावधायी निधि-सैब" (जीपीएफ सैब) से अभिप्राय राजस्थान वित्त</p>
--	--

	<p>निगम में नियुक्त कर्मचारियों पर लागू सामान्य प्रावधायी निधि के योजना के प्रावधानों से है जब तक कि अन्यथा कोई प्रावधान नहीं किया जाये।</p> <p>(xvi) "एसआईपीएफ पोर्टल" यह एक विभागीय वेब बेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से सामान्य प्रावधायी निधि योजना के लेखों का संधारण, भुगतान तथा अभिदाता के सम्पूर्ण कार्यों का ऑनलाईन संधारण एवं निस्तारण किया जायेगा।</p> <p>(xvii) "भुगतान प्रक्रिया" से अभिप्राय यह प्रक्रिया है जो राज्य सरकार के विभिन्न नियमों, आदेशों, एसआईपीएफ पोर्टल, आईएफएमएस तथा संबंधित अन्य आदेशों/प्रक्रियाओं से निर्धारित की जाये।</p>
3.	<p>प्रावधायी निधि योजना में अभिदान:-</p> <p>(i) सामान्य प्रावधायी निधि योजना में अनिवार्य अभिदान:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. राजस्थान वित्त निगम का कर्मचारी जो जीपीएफ लिंकड पेंशन स्कीम को अंगीकृत करता है वह प्रावधायी निधि योजना में अनिवार्य रूप से 12 प्रतिशत की दर से अभिदान करेगा। 2. यह अभिदाता जो सेवा निवृत्ति के बाद एक बार में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए विहित प्रक्रिया द्वारा नियमित रूप से (On roll) नियुक्त किये गये हों वे भी अभिदान करेंगे। <p>(ii) सामान्य प्रावधायी निधि-सैब (जीपीएफ-सैब) के कार्मिक सामान्य प्रावधायी निधि योजना में स्वैच्छिक अभिदान कर सकेंगे। यदि ये कार्मिक स्वैच्छिक अभिदान का विकल्प नहीं चुनते हैं तो राजस्थान वित्त निगम के आदेशों के अनुरूप जो कटौती की जायेगी वही कटौती की जायेगी।</p>
4.	<p>सेवा निवृत्ति पश्चात खाताधारक को खाता चालू रखने का विकल्प:-</p> <p>(i) खाताधारक को यह विकल्प होगा कि वह सेवानिवृत्ति के पश्चात प्राप्त सेवानिवृत्ति परिलाभों की राशि तक यथा सेवानिवृत्ति उपादान, पेंशन रूपान्तरण, उपार्जित अवकाश के नकदीकरण, प्रावधायी निधि स्वत्व राशि, प्रावधायी निधि खाते में जमा करा सकेंगे। इस जमा राशि एवं अर्जित ब्याज पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कर, यदि कोई हो, के भुगतान का उत्तरदायित्व संबंधित खाताधारक का होगा।</p> <p>(ii) बोर्ड द्वारा सक्षम आदेशों से अन्य कार्मिकों/पेंशनर को इस हेतु सम्मिलित किया जा सकेगा।</p> <p>(iii) उपरोक्त विनियमन 4 (i) एवं (ii) में उल्लेखित अवधि में खातेदार अपने खाते से आवश्यकतानुसार कुल जमा राशि की सीमा तक आहरित कर सकेगा।</p>
5.	<p>नाम निर्देशन:-</p> <p>(i) निधि में सम्मिलित होते समय अभिदाता एक अथवा अधिक व्यक्तियों के पक्ष में एसआईपीएफ पोर्टल पर निर्धारित फील्ड में ऑनलाईन नाम निर्देशन करेगा, जिसे उसके खाते में जमा रकम के संदेय होने से पूर्व या जहां रकम संदेय हो गई हो तो उसके भुगतान होने से पूर्व अभिदाता की मृत्यु होने की दशा में निधि में जमा रकम प्राप्त करने का अधिकार होगा।</p> <p>परन्तु यदि अभिदाता अवयस्क हो तो उसके वयस्क होने पर ही नाम निर्देशन किया</p>

	<p>जाना आवश्यक होगा। परन्तु नाम निर्देशन पंजीकृत कराते समय अभिदाता का परिवार होने की स्थिति में वह परिवार के सदस्य/सदस्यों के पक्ष में ही नाम निर्देशन कर सकेगा।</p> <p>परन्तु यह भी कि, निधि में सम्मिलित होने से पूर्व किसी अन्य प्रावधायी निधि में संदाय करने वाले अभिदाता द्वारा उस निधि में पंजीकृत करवाया गया नाम निर्देशन, यदि उस निधि में जमा राशि इस निधि में अन्तरित कर दी गई है, तो इन नियमों को अंतर्गत जब तक वह नया नाम निर्देशन नहीं करता, इन नियमों में किया हुआ माना जायेगा।</p> <p>अभिदाता द्वारा विवाह पूर्व किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किया गया नाम निर्देशन विवाह पश्चात नया मनोनयन नहीं करने की स्थिति में उसके पत्नि/पति के पक्ष में स्वतः ही किया हुआ समझा जायेगा।</p>
(ii)	यदि अभिदाता उपरोक्त उप विनियमन (i) के अन्तर्गत एक से अधिक व्यक्तियों का नाम निर्देशन करता है तो मनोनयन में प्रत्येक मनोनीत को प्राप्त होने वाली राशि या उसके भाग को इस प्रकार निर्दिष्ट करेगा कि निधि में किसी भी समय जमा उसकी सम्पूर्ण राशि इसके अन्तर्गत समाहित हो जाये।
(iii)	अभिदाता किसी भी समय पूर्व में किये गये नाम निर्देशन को निरस्त कर प्रावधानों के अनुरूप ऑनलाइन नया नाम निर्देशन कर सकेगा।
(iv)	<p>अभिदाता नाम निर्देशन में प्रावधान कर सकता है कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. किसी विनिर्दिष्ट मनोनयन के संदर्भ में, मनोनीत की अभिदाता से पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में, उस मनोनीत के अधिकार मनोनयन प्रपत्र में निर्दिष्ट किये गए अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को हस्तान्तरित होंगे परन्तु यदि अभिदाता के परिवार में अन्य सदस्य है तो ऐसा मनोनयन परिवार के सदस्य/सदस्यों के लिए ही मान्य होगा। इस खण्ड के अन्तर्गत यदि अभिदाता ऐसा अधिकार एक अधिक व्यक्तियों का प्रदान करता है तो वह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होने वाली राशि/भाग का निर्धारण इस प्रकार करेगा कि पूर्व में मनोनीत को प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण राशि/भाग इसके अन्तर्गत समाहित हो जायें। 2. मनोनयन में किसी निर्दिष्ट आकस्मिक घटना के घटित होने की स्थिति में मनोनयन अवैध हो जायेगा। <p>परन्तु मनोनयन पंजीकृत कराते समय यदि अभिदाता के परिवार में केवल एक ही सदस्य है तो वह मनोनयन में प्रावधान करेगा कि उपरोक्त खण्ड (i) में वैकल्पिक मनोनीत को प्रदत्त अधिकार परिवार के अन्य सदस्य/सदस्यों के परिवार में शामिल हो जाने पर अमान्य हो जायेंगे।</p>
(v)	ऐसे मनोनीत की मृत्यु की दशा में, जिसमें मनोनयन में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया हो या किसी घटना के घटित होने पर मनोनयन अमान्य हो जाता है, इन विनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत पुराना मनोनयन निरस्त करते हुए नया मनोनयन दर्ज करेगा।
(vi)	अभिदाता द्वारा किये गये मनोनयन एवं निरस्तीकरण ऑनलाइन मनोनयन एवं

	<p>निरस्तीकरण के प्राप्त होने की तिथि से प्रभावी होंगे।</p> <p>(vii) मनोनीत पर खातेदार की हत्या अथवा हत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप होने पर जीपीएफ खाते में जमा राशि का भुगतान न्यायालय का निर्णय होने तक लंबित रखा जायेगा। न्यायालय का निर्णय होने पर यदि मनोनीत पर हत्या अथवा हत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप सिद्ध होता है तो जीपीएफ खाते में जमा राशि का भुगतान परिवार के अन्य सदस्यों को किया जायेगा। मनोनीत निर्देशिनी पर हत्या अथवा हत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप सिद्ध नहीं होता है एवं सरकार आगे अपील में नहीं जाने का निर्णय लेती है तो जीपीएफ खाते में जमा राशि का भुगतान मनोनीत को किया जायेगा।</p>
6.	<p>निधि का लेखा एवं इसका अंकेक्षण :-</p> <p>(i) अभिदाताओं से प्राप्त सभी प्राप्तियां सामान्य प्रावधायी निधि में जमा की जायेगी एवं सभी आहरण इस निधि के नामे लिखे जायेंगे।</p> <p>(ii) सरकार प्रति वर्ष वित्तीय वर्ष के आरंभ में निधि के खाते में अवशेष जमा राशि पर एक वर्ष का एवं वर्ष के दौरान शुद्ध प्राप्तियों पर मासिक गुणन के आधार पर समय-समय पर निर्दिष्ट दर से ब्याज जमा करेगी। प्राप्ति/आहरण जिस तिथि को किया गया है, उसी तिथि के अनुसार ब्याज की गणना की जायेगी जब तक राज्य सरकार के अन्यथा कोई आदेश नहीं हो।</p> <p>(iii) निधि के खाते प्रति वर्ष 30 जून तक बंद किये जायेंगे और महालेखाकार, राजस्थान द्वारा अंकेक्षित किये जायेंगे।</p>
7.	<p>निधि की प्रशासनिक सूचना :-</p> <p>गत वित्तीय वर्ष के दौरान प्रावधायी निधि योजना की प्रशासनिक एवं कार्य कलापों की रिपोर्ट प्रति वर्ष 30 सितम्बर से पूर्व निदेशक द्वारा सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।</p>
8.	<p>अभिदाता द्वारा प्रथम जमा :-</p> <p>(i) सामान्य प्रावधायी निधि-सैब के अन्तर्गत आने वाले कार्मिक स्वैच्छिक अभिदान का विकल्प चुनकर प्रथम कटौती जमा करा सकेंगे।</p> <p>(ii) यदि ये कार्मिक स्वैच्छिक अभिदान का विकल्प चुनते हैं तो भविष्य में अनिवार्य अभिदान किया जाना आवश्यक होगा।</p> <p>(iii) यदि ये कार्मिक स्वैच्छिक अभिदान का विकल्प नहीं चुनते हैं तो राजस्थान वित्त निगम के आदेशों के अनुरूप जो कटौती की जायेगी वह इन कार्मिकों हेतु प्रथम कटौती होगी।</p>
9.	<p>खाता संख्या एवं पास बुक :-</p> <p>(i) एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से ऑन लाइन वेतन से प्रथम बार राशि कटौती उपरान्त जमा होने पर कर्मचारी को सिस्टम जनरेटेड खाता संख्या आवंटित होगी।</p> <p>(ii) अभिदाता की जमा राशि का ई-पासबुक में इन्द्राज नहीं होने तक लुप्त कटौतियों के लिये कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित पासबुक/एसआईपीएफ पोर्टल पर प्रदर्शित स्कैन प्रति (Scanned copy) अंतिम साक्ष्य</p>

	के रूप में माना जायेगा।
10.	<p>खाते में जमा की जाने वाली राशि:-</p> <p>(i) राजस्थान वित्त निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से इन विनियमनों के नियम 3 (ii) के अतिरिक्त कर्मचारियों द्वारा उनके वेतन से अनिवार्य मासिक अभिदाय किया जायेगा परन्तु निलम्बन की अवधि में अभिदाय की राशि की कटौती नहीं की जायेगी। अभिदाता के वेतन से राशि आहरित किया जाकर वहां अभिदाय की निर्धारित राशि ऑन लाईन प्रक्रिया से जमा करवाई जायेगी।</p> <p>(ii) राजस्थान वित्त निगम द्वारा जमा कराये जाने के लिए आदेशित अन्य कोई राशि।</p> <p>(iii) उपरोक्त वर्णित राशि एवं अन्य अनिवार्य कटौतियों को कम करने के पश्चात वार्षिक परिलब्धियों में शेष राशि तक स्वैच्छिक तौर पर जमा कराई जा सकेगी।</p>
11.	<p>जमा का बंद होना:-</p> <p>(i) अभिदाता की मृत्यु, सेवा से त्याग पत्र, पदच्युत कर दिये जाने, हटाये जाने, सेवानिवृत्ति से पूर्व अवकाश पर जाने पर कटौती बंद हो जायेगी।</p> <p>(ii) अभिदाता की सेवानिवृत्ति से एक माह पूर्व उसकी कटौती बंद हो जायेगी।</p>
12.	<p>राशि जमा कराये जाने की प्रक्रिया:-</p> <p>(i) पूर्व नियुक्त कर्मिकों के लिए कार्यालयाध्यक्ष संबंधित अभिदाता के वेतन से निर्धारित दर से मासिक अभिदाय की कटौती किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त राजस्थान वित्त निगम के आदेशों से जमा राशि एवं अभिदाता द्वारा स्वयं के विकल्प के अनुसार जमा कराने हेतु प्रस्तावित राशि अभिदाता द्वारा जमा कराई जा सकेगी। यह राशि वर्ष के दौरान उसकी कुल वार्षिक परिलब्धियों में से उपरोक्त वर्णित राशि एवं अन्य अनिवार्य कटौतियों को कम करने के पश्चात शेष राशि की सीमा तक होगी। यह कटौतियां निर्धारित प्रक्रियानुसार जमा कराई जा सकेंगी।</p> <p>(ii) सामान्य प्रावधानी निधि योजना सैब के अन्तर्गत अभिदान करने वाले अंशदान इस योजना में अभिदान हेतु विकल्प चुनते हैं तो वे कार्यालयाध्यक्ष को ऑन लाइन एडवाइज प्रस्तुत करेंगे एवं कार्यालयध्यक्ष संबंधित अभिदाता के वेतन से निर्धारित दर से मासिक अभिदाय की मासिक कटौती की जायेगी। इसके राजस्थान वित्त निगम के आदेशों से जमा राशि एवं अभिदाता द्वारा स्वयं के विकल्प के अनुसार जमा कराने हेतु प्रस्तावित राशि अभिदाता द्वारा जमा कराई जा सकेगी। यह राशि वर्ष के दौरान उसकी कुल वार्षिक परिलब्धियों में से उपरोक्त वर्णित राशि एवं अन्य अनिवार्य कटौतियों को कम करने के पश्चात शेष राशि की सीमा तक होगी।</p>
13.	<p>ब्याज:-</p> <p>(i) ब्याज कब जमा किया जाता है:-</p> <p>1. वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में प्रारम्भिक शेष पर अप्रैल माह में अभिदाता के खाते में ब्याज जमा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के दौरान की गई जमाओं के लिये जिस माह में राशि जमा की गई है उसकी ब्याज की गणना मासिक गुणन के आधार पर आगामी माह में की जाकर अभिदाता के खाते में ब्याज जमा किया जायेगा। ब्याज की गणना करते समय आहरण को आहरित करने के माह में समायोजित किया</p>

<

	<p>अथवा जमा का 50 प्रतिशत जो भी कम हो तक की सीमा में ही आहरण किया जा सकेगा।</p> <p>2 75 प्रतिशत 1. भवन निर्माण, भू-खण्ड क्रय, आवास क्रय, फ्लैट क्रय, निर्मित या अधिग्रहित भवन या आवास पुनर्निर्माण, विस्तार, परिवर्धन, भू-खण्ड पर भवन निर्माण</p> <p>2. अभिदाता की स्वयं या उसके पुत्रों/पुत्रियों की सगाई/विवाह हेतु।</p> <p>3. अन्य कारण जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आदेशित किये जावें।</p> <p>(ii) आहरण हेतु राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग के स्तर पर किसी प्रकार की स्वीकृति एवं राजस्थान वित्त निगम स्तर पर जांच अथवा अधिकृति की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। बाधारहित आहरण Direct Benefit Transfer (DBT) /सर्वर सर्टिफिकेट के माध्यम से बैंक खाते में हस्तांतरित किया जा सकेगा।</p> <p>(iii) राजस्थान वित्त निगम द्वारा समय समय पर आदेश जारी कर खातेदार के सेवाकाल /आय के अनुसार आहरण की सीमा तथा आहरण के कारणों को संशोधित /पुनर्निर्धारित किया जा सकेगा।</p> <p>(iv) कोई भी अभिदाता अपने खाते से UPI (Unified Payments Interface) के माध्यम से UPI की मानक शर्तों SOP (Standard Operating Procedures) के अनुसार भी आहरण कर सकेगा।</p> <p>(v) अभिदाताओं को आहरण स्वीकृति/भुगतान के संबंध में राजस्थान वित्त निगम में प्रबन्ध निदेशक के स्तर पर समय-समय पर यथावश्यक प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी।</p>
15.	<p>अभिदाता के सेवानिवृत्त अथवा सेवामुक्त होने पर खाता बंद होने की प्रक्रिया:-</p> <p>(i) अभिदाता के खाते में जमा राशि मय ब्याज भुगतान हो जाने पर अभिदाता का खाता बंद कर दिया जायेगा।</p> <p>(ii) निदेशक खाता बंद किये जाने वाले वर्ष के दौरान लिये गये आहरण को कम करते हुए अभिदाता के खाते में जमा राशि पर भुगतान करने से पूर्व माह तक के ब्याज सहित जमा राशि का भुगतान करेगा।</p> <p>(iii) केवल मृत्यु के मामलों को छोड़कर अन्य समस्त मामलों में भुगतान अभिदाता को किया जावेगा। अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में भुगतान नियम 16 के अनुरूप किया जायेगा।</p> <p>(iv) अंतिम भुगतान प्राप्त करने हेतु अभिदाता ऑनलाईन क्लेम रिक्वेस्ट के साथ undertaking हेतु निर्धारित चैक बॉक्स में सहमति प्रस्तुत करेगा जिसके अनुसार निधि से अधिक भुगतान होना पाये जाने पर राशि जीपीएफ की</p>

	तत्समय प्रचलित ब्याज दर सहित एक मुश्त लौटाने हेतु बाध्य होगा।
16.	<p>अभिदाता की मृत्यु पर प्रक्रिया:-</p> <p>(1) अभिदाता द्वारा अपने पीछे परिवार छोड़ने की दशा में :-</p> <p>(i) यदि अभिदाता द्वारा नियम 5 के या इससे पूर्व प्रवृत्त तदनुरूपी नियम उपबन्धों के अनुसार अपने परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में किया गया नाम निर्देशन अस्तित्व में है, तो निधि में अभिदाता के खाते में जमा रकम या उसका कोई अंश, जो नाम निर्देशन से संबंधित है, नाम निर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में उसके नाम निर्देशित या नाम निर्देशितियों को संदेय हो जायेगा।</p> <p>(ii) यदि अभिदाता के परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में कोई नाम निर्देशन अस्तित्व में नहीं है, या यदि ऐसा नाम निर्देशन निधि में उसके खाते में जमा रकम के एक अंश से ही सम्बन्धित है, तो सम्पूर्ण रकम या उसका अंश, जो नाम निर्देशन से सम्बन्धित नहीं है, जैसी भी स्थिति हो, उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किये जाने हेतु तात्पर्यित किसी नाम निर्देशन के होते हुए भी उसके परिवार के तत्समय जीवित सदस्यों को समान अंशों में संदेय हो जायेगा तथापि यदि कोई विवाद हो और विभाग वारिसों के बारे में विनिश्चय करने की स्थिति में नहीं हो तो दावे के संदाय हेतु एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाईन क्लेम रिक्वेस्ट सबमिट की जायेगी और जांच उपरान्त पात्र होने पर उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करनेवाले व्यक्ति/व्यक्तियों को दावे का संदाय किया जायेगा।</p> <p>(2) अभिदाता द्वारा अपने पीछे परिवार न छोड़ने की दशा में :-</p> <p>(i) यदि नियम 5 के या इससे पूर्व प्रवृत्त तदनुरूपी नियम के उपबन्धों के अनुसरण में किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के पक्ष में अभिदाता द्वारा किया गया नाम निर्देशन अस्तित्व में हो तो निधि में अभिदाता के खाते में जमा रकम या उसका कोई अंश, जो नाम निर्देशन से सम्बन्धित है, नाम निर्देशित या नाम निर्देशितियों को, नाम निर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में संदेय हो जावेगा।</p> <p>(ii) अभिदाता के लापता होने पर खातेदार के विभाग द्वारा जारी सेवामुक्ति आदेश अथवा न्यायालय द्वारा मृतक घोषित किये जाने के आदेश प्राप्त होने पर जीपीएफ में जमा राशि का भुगतान किया जायेगा।</p> <p>(iii) अभिदाता के खाते में जमा रकम के संदेय होने से पूर्व या जहां रकम संदेय हो गई है तो, संदाय होने से पूर्व अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर वैध मनोनीत/दावेदार की ओर से प्रमाणिक दस्तावेजों के आधार पर एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाईन क्लेम रिक्वेस्ट सबमिट की जायेगी और जांच उपरान्त पात्र होने पर संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों को दावे का संदाय किया जायेगा।</p> <p>(iv) अभिदाता की मृत्यु होने पर अंतिम भुगतान हेतु मनोनीत /दावेदार ऑनलाईन क्लेम रिक्वेस्ट के साथ ऑन लाईन undertaking हेतु निर्धारित चैक बॉक्स में सहमति प्रस्तुत करेगा, जिसमें अंतिम भुगतान प्राप्त करने हेतु जिसके अनुसार निधि से अधिक भुगतान होना पाये जाने पर राशि जीपीएफ की तत्समय प्रचलित ब्याज दर</p>

	सहित एक मुश्त लौटाने हेतु बाध्य होगा।
17.	<p>किसी भी न्यायालय द्वारा खाता अधिग्रहित/कुर्क न करना:-</p> <p>इन नियमों के अनुसरण में सामान्य प्रावधायी निधि के अन्तर्गत भुगतान योग्य राशि अधिग्रहण और/या किसी डिक्री के क्रियान्वयन के लिये कुर्की से मुक्त है और ऐसी सम्पूर्ण राशि इस तथ्य को नजर अंदाज करते हुए कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के कारण यह किसी अन्य व्यक्ति को देय है, अधिग्रहण से मुक्त रहेगी।</p>
18.	<p>प्रबन्धन व्यय:-</p> <p>प्रावधायी निधि योजना के प्रबन्धन के लिए आवश्यक व्यय राशि सरकार द्वारा सरकार में जमा प्रावधायी निधि पर देय ब्याज के अतिरिक्त बजट में प्रावधित की जाकर उपलब्ध कराई जावेगी।</p>
19.	<p>अन्तिम भुगतान के मामले में शक्तियों का प्रत्योजन:-</p> <p>(i) विभाग के संयुक्त/उप/सहायक निदेशक इन नियमों के नियम 15 एवं 16 के अन्तर्गत अंतिम भुगतान योग्य राशि पर भुगतान आदेश जारी करने के पूर्ववर्ती माह तक ब्याज स्वीकृत करने के लिए अधिकृत होंगे।</p> <p>(ii) इन नियमों के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के अभिदाता होने के पात्र न होने की स्थिति में उससे प्राप्त राशि विभाग के संयुक्त/उप/सहायक निदेशक उक्त राशि विभाग में जमा रहने की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट की गई दर से ब्याज सहित लौटाने के लिए अधिकृत होंगे।</p>
20.	<p>निर्वचन:-</p> <p>इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है तो राज्य सरकार के वित्त विभाग को निर्णय हेतु भेजे जायेंगे।</p>
21.	<p>शिथिलता प्रदान करने की शक्ति:-</p> <p>जहां राज्य सरकार सन्तुष्ट है कि इन नियमों के क्रियान्वयन से किसी विशेष प्रकरण में अनावश्यक कठिनाई उत्पन्न होने पर, ऐसे प्रकरणों में वह कारणों को लिपिबद्ध करते हुए सम्बंधित नियम में आवश्यक सीमा तक वित्त विभाग की सक्षम सहमति से शिथिलन प्रदान कर सकती है।</p>
22.	<p>प्रत्यायोजन की शक्तियां :-</p> <p>राज्य सरकार अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को इन नियमों के अन्तर्गत नियम 15 एवं 16 के अतिरिक्त, आवश्यक शर्तों के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकेगी।</p>
23.	<p>उपरोक्त "राजस्थान वित्त निगम कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि विनियम-2023" में जहाँ जहाँ राज्य सरकार के नियमों से अन्तर या व्याख्या का प्रश्न है तो राज्य सरकार के नियमों में उल्लेखित प्रावधान लागू रहेंगे।</p>

	यदि वित्त निगम द्वारा संदर्भित नियमों से भिन्न विनियमों के अन्तर्गत कोई प्रावधान किया जाता है तो इस संदर्भ से राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
--	---

संचालक मण्डल की आज्ञा से,
(डा. के.के.गुप्ता)
महाप्रबन्धक एवं सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।